मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 23 अंक : 10

5 जून 2023

महाकाल लोक में महा घोटाला

हर बिल में डील है

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
दिल्ली संवाददाता	नीरज दिवाकर
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
छत्तीसगढ़ संवाददाता	मणिशंकर पाण्डेय
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 23 अंक 10 05 जून 2023

महाकाल लोक में महा घोटाला

(पृष्ठ क्र.-6)

■ चीतों की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मदार? 49

■ पहाड़ों के जंगलों में आग 53

■ मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन? 56

■ Marriage with a worksholic 60

कांग्रेस में सिर्फ मैं ही मैं!
विजया :)

चुनावी वर्ष में मुफ्त वाली घोषणाएं और उसका महत्व

भारत में चुनावों के दौरान लोक लुभावन वादे करना एवं चुनाव जीतने पर भूल जाने की संस्कृति नई नहीं रही है। जनता को मुफ्त की रेवड़ी की सर्वप्रथम शुरुआत तत्कालीन आंध्रप्रदेश में एनटी रामाराव द्वारा की गई। जब उन्होंने दो रुपए किलो चावल देने की घोषणा की। उसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में इसका वृहत्तर स्वरूप देखने को मिला। वहां दोनों ही क्षेत्रीय दलों द्वारा जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एक से बढ़कर एक लोक-लुभावन घोषणाएं की जाती रही हैं। 100 यूनिट फ्री बिजली, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, कामकाजी महिलाओं को स्कूटी खरीदने में सब्सिडी से लेकर प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइन्डर, मंगलसूत्र तक देने की भी घोषणा की गई। भारत जैसे देश में जहां बड़े पैमाने पर गरीबी व्याप्त है क्या वास्तव में ऐसी घोषणाएं दीर्घकाल में भी जनता की गरीबी दूर करने में सफल होगी? क्योंकि जनता की वास्तविक गरीबी दीर्घकालीन एवं सुनियोजित नीतियों के माध्यम से ही दूर हो पाएगी न कि इस तरह की चुनावी घोषणाओं एवं योजनाओं से। यदि हम राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही मुफ्त घोषणाओं को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि समय के साथ मुफ्त घोषणाओं में हमें मौलिक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। प्रारम्भ में मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा इत्यादि की घोषणाएं होती थी किन्तु अब तमिलनाडु के पैटर्न पर दूसरे राज्यों में भी टीवी, मोबाइल, स्मार्टफोन, टेबलेट, लैपटॉप, ऋण माफी की बातें हो रही हैं जिन्हें यदि पूरी तरह वास्तविक धरातल पर उतारा जाए तो राज्यों की अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। हाल ही में कर्नाटक में नवगठित कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही चुनाव में किए गए 05 वायदों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इन पांच वायदों में हर गृहिणी को 2000 रुपए प्रति माह भत्ता, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, गरीब परिवारों को हर महीने 10 किलो चावल और महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा के अलावा डिप्लोमाधारक बेरोजगारों को हर माह 1500 रुपए और डिग्रीधारकों को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 05 वायदों की पूर्ति के चलते राज्य सरकार के खजाने पर हर साल करीब 50 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जबकि कर्नाटक का बजट 61,564 करोड़ के घाटे का है। कर्नाटक को मुफ्त की रेवड़ी की घोषणा के बाद अन्य रायों में भी राजनीतिक दलों ने इस तरह के लोकलुभावन वायदे करना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इसे सफलता का राजनीतिक सूत्र बनाया था। कर्नाटक की कामयाबी से उत्साहित होकर कांग्रेस ने मध्यप्रदेश से लेकर हरियाणा में इस तरह की योजनाओं की घोषणा की है। हरियाणा में तो कांग्रेस ने 100 गज के भूखंड देने की घोषणा की है। आखिर जमीन जैसे दुर्लभ संसाधन को लेकर कोई पार्टी किस प्रकार ऐसा वायदा कर सकती है। इस तरह की लोकलुभावन नीतियां दीर्घकाल में लाभकारी नहीं हो सकतीं तथा अर्थव्यवस्था पर बोझ डालती हैं एवं मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती हैं। इसके अतिरिक्त, बड़े राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी घोषणाएं किसी भी राज्य में छोटे दलों को समान अवसर नहीं उपलब्ध कराएंगी क्योंकि वे क्षेत्र विशेष तक सीमित होने के कारण बड़े लोकलुभावन वायदे नहीं कर पाएंगे।

विजया पाठक

महाकाल लोक में महा घोटाला

देश में कैसे आस्था पर भी डाका डाला जा सकता है, यह उज्जैन महाकाल लोक घोटाला से साबित होता है। उज्जैन महाकाल लोक घोटाला भ्रष्टाचार और निर्माण जल्दबाजी का एक ऐसा संगम था जिसने देश में वाहवाही तो लूटी पर उसकी परतों में करीब 300 करोड़ का भ्रष्टाचार छिपा है। जगत विजन ने जब इस घोटाले की पड़ताल की तो हम हैरत में पड़ गए, कि कैसे सरकार ने भगवान शिव (महाकाल) ने नाम पर करीब–करीब हर बिल में भ्रष्टाचार किया। कैसे महाकाल के प्रकोप की चिंता किए बगैर निर्लज्जता से पैसे खाए गए शायद इसी से रूष्ट होकर भगवान महाकाल स्वयं ने ही इन भ्रष्टाचारियों की पोल खोल कर रख दी। महाकाल लोक की सिर्फ यह मूर्तियां ही खंडित नहीं हुई हैं बल्कि प्रदेश सरकार के इस भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता की आस्था भी खंडित हुई है। निश्चित तौर पर महाकाल का डमरू बजेगा, शिव तांडव होगा और उनके भक्त ही इसका जवाब अब हर भ्रष्टाचारी को देंगे। हस्यास्यद बात यह है कि तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने मूर्तियों की उम्र 100 वर्ष बताई थी, मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रेस के सामने कहा कि मूर्ति तेज आंधी की वजह से गिरी और कंस्ट्रक्शन एजेंसी से 03 साल मेंटनेंस का एग्रीमेंट है जबकि उज्जैन कलेक्टर ने 10 साल का बताया। या तो मंत्री झूठ बोल रहे हैं या उज्जैन कलेक्टर झूठ बोल रहे है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पत्थर की मूर्तिया के मुकाबले प्लास्टिक की मूर्तियां ज्यादा आकर्षक लगती हैं। इसका मतलब अयोध्या में श्रीरामलला जन्मभूमि में और काशी विश्वनाथ कॉरीडोर में बनी पत्थर की मूर्तियां एफआरपी (प्लास्टिक) से कम मोहक है। जांच करने का मुख्य मुद्दा यह है कि महाकाल लोक में हुये इस व्यापक भ्रष्टाचार जोकि तब के कलेक्टर आशीष सिंह के कार्यकाल में हुआ उनको किसका राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है। विभागीय मंत्री भूपेन्द्र सिंह की इस पूरे निर्माण में क्या भूमिका रही और किसके कहने पर आशीष सिंह को एलीवेट किया गया। जल्दबाजी के चक्कर में भ्रष्ट अधिकारियों ने करीब–करीब हर टेंडर में पैसे कमाए। असली मूर्तियां जो पत्थर या ग्लास फाइबर की बननी थी उन्हें प्लास्टिक फाइबर से क्यों बनाया गया जबकि महाकाल ज्योतिर्लिंग एक तीर्थ स्थल है। आलम यह रहा कि महाकाल लोक में मूर्ति बनाने वाली कंपनी ने उज्जैन में भगवान झूलेलाल की उसी मटेरियल की मूर्ति के लिए 16 गुना कम पैसे लिए। महाकाल लोक प्रधानमंत्री मोदी के धार्मिक–आध्यात्मिक संकल्प में शामिल है, जिसमें बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या श्री राम लला मंदिर भी है। एक तरफ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनारस में सारे काम नियमानुसार हुए, मूर्तियों एवं अन्य स्वरूप में पाषाण/पत्थर का उपयोग हुआ और एक अमर कॉरिडोर चरितार्थ हुआ है। वैसे ही श्री राम लला मंदिर अयोध्या में सारी मूर्तियां पाषाण/पत्थर की बनाई गई। देश के प्रमुख शिल्पकार जैसे सुदर्शन साहू (ओडिसा), गणेश एल भट्ट (कर्नाटक), सत्यनारायण पांडे (राजस्थान) और अरुण योगिराज (कर्नाटक) मूर्तियां बना रहे हैं। इसके उलट महाकाल लोक में इंदौर स्थित आर्किटेक्ट नितिन श्रीमाली और महिला शिल्पकार संगीता बैंस को रखा गया। जल्दबाजी और भ्रष्टाचार के कारण प्लास्टिक फाइबर से मूर्तियों का निर्माण हुआ जिसमें एक वर्ष के अंदर ही त्रुटियां दिखने लगी हैं। लगभग हर बिल में पैसे बढ़ाकर एस्टीमेट बनाया गया और भुगतान हुआ। निर्माण के समय हालत यह थी कि नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता को महाकाल लोक के उद्घाटन के 10 दिन पहले ट्रांसफर कर दिया गया। इसकी पूरी जिम्मेदारी तब के कलेक्टर आशीष सिंह पर बनती है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार बगैर राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। यह निर्माण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत था जिसके विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं जो कि मुख्यमंत्री के सबसे खास हैं और महाकाल लोक के निर्माण में उज्जैन में कैम्प कर रखा था। महाकाल लोक निर्माण के दौरान मूर्तियों की क्वालिटी को लेकर तब उज्जैन मीडिया में प्रकाशन भी हुआ पर सरकार ने उसके बाद भी आशीष सिंह को फ्री हैंड देकर रखा। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस विधायक महेश परमार ने अंशुल गुप्ता के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की, जिसे लोकायुक्त ने परीक्षण करने के पश्चात कुल 15 लोगों को नोटिस दिए जिसमें प्रमुख कलेक्टर आशीष सिंह थे। मामला संदेहास्पद इसलिए भी लग रहा है कि जिस अधिकारी के कार्यकाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, लोकायुक्त ने जिसे भ्रष्टाचार को लेकर नोटिस दिया हो उसे राजनीतिक संरक्षण के कारण पहले एमपीआरडीसी का एमडी बनाया गया और बाद में भोपाल कलेक्टर का पद देकर एलिवेट किया गया है। इस पूरे मामले से निष्कर्ष यही निकलता है कि महाकाल लोक घोटाला में सरकार भी शामिल रही है वरना जिस अधिकारी पर कार्यवाही करनी चाहिए थी उसे क्यों एलीवेट किया गया। मामले में निश्चित ही केंद्र भी हस्तक्षेप करेगा क्योंकि महाकाल लोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 कैंपेन का प्रमुख हिस्सा है। जहां भाजपा एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति कर रही है वैसे में उसकी सरकार ने भगवान महाकाल के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। प्रदेश में काफी सारे लोकों का निर्माण की घोषणा सरकार द्वारा की गई है जो अब संदेह पैदा करती हैं कि कहीं यह पैसा खाने की स्कीम तो नहीं क्योंकि धार्मिक मामलों में चीज़ें ढकी रहती हैं। भगवान श्री महाकाल में हुए इस घोटाले के कारण महाकाल प्रदेश से रुष्ठ होकर विधानसभा चुनावों में तांडव ना कर दे क्योंकि यह घोटाला महाकाल के भक्तों की आस्था पर हुआ है।

महाकाल लोक : आधी

विजया पाठक

उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर की भव्यता चर्चा में है। जिस बड़े पैमाने पर महाकाल कॉरिडोर में विकास और सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, उसकी खूब तारीफ हो रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकाल कॉरिडोर को विकसित करने में सरकार ने कितना खर्च किया है? क्या वाकई में इसके निर्माण में जितना खर्च हुआ है उसका सदुपयोग हुआ है। महाकाल कॉरिडोर को विकसित करने का यह प्रोजेक्ट कुल 1100 करोड़ रुपए से अधिक का है। इसमें पहले चरण में 351 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। वहीं दूसरे चरण में लगभग 850 करोड़ रुपए के काम कराए जाएंगे। 11 अक्टूबर 2022 को मोदी ने पहले चरण में हुए काम का उद्घाटन किया। दूसरे चरण का काम इसी माह यानि जून 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। पहले चरण में मुख्य कॉरिडोर के निर्माण में 224 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं रुद्र सागर में सीवेज सिस्टम के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पार्किंग सोलर पैनल पर 16 करोड़ रुपए और महाकाल द्वार के विकास पर 3.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। महाकाल कॉरिडोर पर खर्च हो रही कुल रकम में से 421 करोड़ रुपए राज्य सरकार, 271 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, महाकाल मंदिर समिति 21 करोड़ और फ्रांस सरकार 80 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन करने के साथ ही महाकाल कॉरिडोर आम जनता के लिए खुल गया है। पूर्व में महाकाल लोक प्रोजेक्ट दोनों चरणों की लागत करीब 700 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 850 करोड़ रुपए से अधिक किया गया था। अब इसकी लागत 11 सौ करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है। महाकाल मंदिर का क्षेत्र 2.82 हेक्टेयर है और महाकाल कॉरिडोर के विकसित होने के बाद यह बढ़कर 47 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें 17 हेक्टेयर की रुद्रसागर झील भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि उज्जैन आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए मंदिर के विजिटर प्लाजा में एक बार में 20 हजार श्रद्धालु रुक सकेंगे। वहीं शहर में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए नई पार्किंग का निर्माण किया गया है। महाकाल लोक के प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 05 साल का समय लगा। महाकाल लोक बनाने का विचार तब आया जब उज्जैन को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था। एक वजह यह भी रही कि

पूर्व में महाकाल लोक प्रोजेक्ट दोनों चरणों की लागत करीब 700 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 850 करोड़ रुपए से अधिक किया गया था। अब इसकी लागत 11 सौ करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है। महाकाल मंदिर का क्षेत्र 2.82 हेक्टेयर है और महाकाल कॉरिडोर के विकसित होने के बाद यह बढ़कर 47 हेक्टेयर हो जाएगा।

हकीकत आधा फ़साना

महाकाल लोक का पहला टेण्डर 97.71 करोड़ का निकला था जिसकी अवधि 18 माह की थी। सरकार ने इसके बाद जो काम 97.71 करोड़ में होना था। सरकार की बदनियति से इसी काम के लिए वापस 196 करोड़ का ठेका निकाला गया। इसके बाद लगभग हर बिल पर भ्रष्टाचार हुआ।

बाबा महाकाल का मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके चलते मंदिर में भीड़ काफी हो जाती है। ऐसे में भक्तों को बाबा के सही से दर्शन मिले इसके लिए महाकाल लोक के निर्माण को बल मिला। लेकिन महाकाल लोक के निर्माणकर्ताओं ने इस प्रोजेक्ट को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। बता दें कि अभी उज्जैन में सालाना करीब डेढ़ करोड़ लोग उज्जैन घूमने और महाकाल के दर्शन करने आते हैं। महाकाल कॉरिडोर के आम जनता के लिए खुलने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 03 करोड़ सालाना तक पहुंच सकता है।

मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने मध्यप्रदेश को लूटने में कोई कमी नही रखी है। आये दिन भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहते हैं। ताजा मामला उज्जैन के महाकाल लोक के निर्माण हो लेकर है। इस महाकाल लोक के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी हुई है। उज्जैन के तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह की सरपरस्ती में निर्माण के सभी प्रकल्पों का घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार कर ठेकेदारों को पैसा दिलवाया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने उज्जैन को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट दिया, जिसमें करोड़ों के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। इसी स्मार्ट सिटी के माध्यम से महाकाल लोक के फेस-1 का निर्माण किया गया है। महाकाल लोक के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त और आर्थिक अपराध शाखा को भी शिकायत की है। जिस पर संज्ञान लिया जा चुका है और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी हो गए हैं। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले शिवराज क्या स्मार्ट सिटी के कर्ताधर्ता पर कार्यवाही करेंगे या इस पर भी चुप्पी साध लेंगे?

आपको बता दें कि महाकाल लोक का पहला टेण्डर 97.71 करोड़ का निकला था जिसकी अवधि 18 माह की थी। सरकार ने इसके बाद जो काम 97.71 करोड़ में होना था। सरकार की बदनियति से इसी काम के लिए वापस 196 करोड़ का ठेका निकाला गया। केन्द्र की सीबीसी गाईडलाईन्स जनरल फिनाईन्स रूल्स के नियमों से कम सुरक्षा जमा राशि निविदा की पृष्ठ क्रमांक 11 पर दिखाया गया। ठेकेदारों को फायदा देने के लिये केन्द्र के नियमानुसार कम सुरक्षा निधि का प्रावधान रखा गया। गौरतलब है कि महाकाल लोक स्मार्ट सिटी के प्रावधान के अंतर्गत बनाया गया और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केन्द्र के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है। महाकाल लोक में एक सौ करोड़ की हेराफेरी की गई। मूल टेण्डर

महाकाल लोक मूर्ति घोटाला

खिलौनों की तरह उड़ गई महाकाल लोक की मूर्तियां....

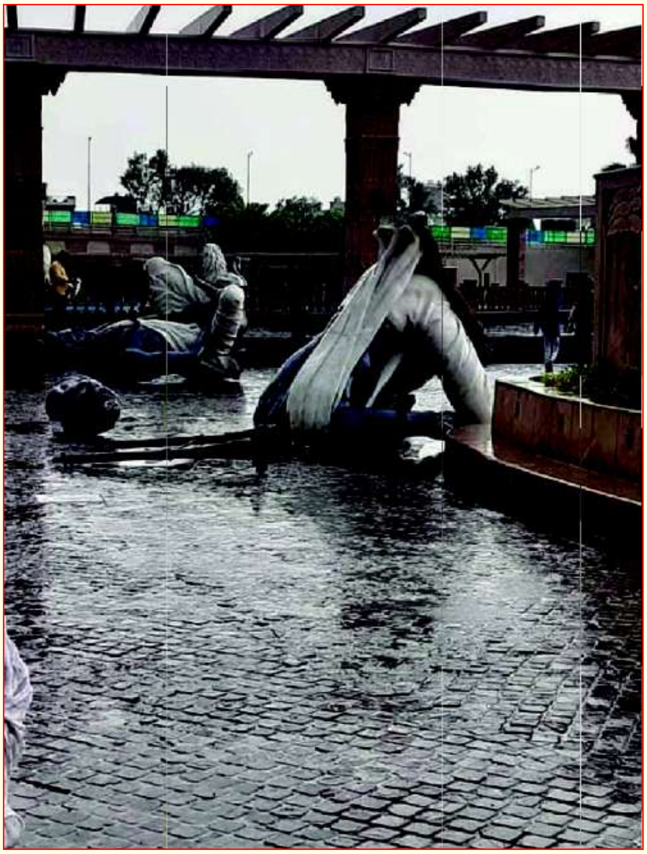

महाकाल लोक में लगी, सप्तऋषियों की ये मूर्तियां मामूली हवा आंधी में उखड़ गई। पत्थर/पाषाण की मूर्ति की जगह प्लास्टिक मूर्तियां आखिर क्यों बनाई गई?

देश में धार्मिक और अध्यात्मिक ट्रांफार्ममेशन के अंतर्गत बनारस स्थित कांशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या स्थित श्रीराम लला जन्म भूमि स्थान में मूर्तियां बनाई जा रही है या स्थापित हो चुकी हैं। यह सभी पाषाण/पत्थर से बनी मूर्तियां हैं। पाषाण/पत्थर से बनी मूर्तियां धर्मानुसार एवं

97.71 करोड़ का हुआ, जिसे ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिये 196 करोड़ का कर दिया गया। यही सबसे बड़ी हेराफेरी है। निर्माण कार्यो और भुगतान में भारी हेराफेरी की गई जनरल फायनेंस कमीशन (एफजीआर) और सेन्ट्रल विजलेंस

अमरतव्य से परिपूर्ण होती है, जोकि हजारों वर्षो तक भक्तों के दिल में समाये रहती हैं। जल्दबाजी, बदनीयती और भ्रष्टाचार के कारण महाकाल लोक की मूर्तियां प्लास्टिक फाईबर से बनाई गई। जबकि मूर्तियां या तो पाषाण/पत्थर की या ग्लास फाईबर की बनानी चाहिए थी। कमल में बैठे हुए सप्तऋषि के केश से मटेरियल झड़ना शुरू हो गया है। इनकी फोटो मैंने बुधवार दिनांक 20 मई, 2023 को खींची थी। फायबर प्लास्टिक से बनी मूर्तियां खिलौनो के समान होती हैं, भ्रष्टाचार की पोल प्रकृति ने ही खोल के रख दी। जिसका साक्षात प्रमाण दिनांक 28 मई, 2023 से

महाकाल लोक की इस तरह हुई दुर्दशा ने दर्शा दिया है कि महाकाल लोक के नाम पर काफी बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है।

साबित हो गया, आंधी में सप्तऋषियों की मूर्तियां उखड़कर दूर गिर गई और खंडित हो गई है। सरकार द्वारा महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का प्रमाण सत्य साबित हुआ। करोड़ों की मूर्तियां कागज़ की तरह उड़ गई। निविदा में स्कोप ऑफ वर्क में पच्चीसों आयटमों का हवाला दिया गया।

कमीशन (सीवीसी) का उल्लंघन किया गया। इस परियोजना में केन्द्र सरकार का पैसा है तो क्यों भारत सरकार से निर्माण व भुगतान पर थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करवाया गया। टेण्डर में इंगित ग्लास फायबर, कांक्रीट और पत्थर की मूर्तियों की जगह

मूर्तियों का अवलोकन करती जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक, इन मूर्तियों में विकृत्ति आना चालू हो गई है।

जिसमें मूर्तियां पत्थर की होनी चाहिए थी। महाकाल लोक में स्थित घोटालों को एस्टीमेट बनवा कर इसमें भी मूल्य वस्तु की कीमत से कई गुना कर बिल पैमेंट किया गया। उल्लेखनीय है कि 1 मई 2022 को सिंधी समाज उज्जैन द्वारा 25 फीट ऊंची मूर्ति जो कि महाकाल लोक के निर्माण ठेकेदारों से ही बनवाई गई थी उसका भुगतान महाकाल लोक के मुकाबले कई गुना कम था। यह एक मुख्य घटना थी जहां से महाकाल लोक में व्याप्त भ्रष्टाचार की पर्ते खुलने की शुरुआत हुई। फाईबर रीइनफोस्ड प्लास्टिक से बनी हुई मूर्तियां हल्की होती है और लाइफ कम रहती है। जिसके कारण मूर्तियां समय के साथ विकृत होती जाती हैं। पत्थर की मूर्तियां तो लगभग अमर होती है ऐसे में महाकाल लोक में शोपीस के जैसे फाईबर रीइनफोस्ड प्लास्टिक की मूर्तियां बनाई

प्लास्टिक फायबर की मूर्तियाँ बनाई गई। शासन की तमाम निर्माण एर्धेसी स्मार्ट

सिटी, पीडब्ल्यूडी, पीआययू, पीएचई व नगर पालिक निगम से कराये जाने वाले

निर्माण कार्यो पर इन्हें सुपर विजन चार्ज नहीं देना होता है, किंतु उज्जैन विकास

भगवान शिव की कमल कुण्ड में स्थापित मूर्ति में विकृत्ति आने लगी है।

जाना महाकाल के भक्तों के साथ छलावा करने के जैसा रहा है। मूर्तियां प्लास्टिक की बनाई जाने का मुख्य उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार रहा है नही तो कैसे डेढ़ वर्ष के अंदर मूर्तियों में विकृति आने लगी। कमलकुण्ड में स्थापित भगवान शिव की मूर्ति का रंग उड़ गया है एवं झड़ना भी शुरू हो गया। श्रीगणेश की मूर्ति में जनेऊ के पास एवं हाथ के पास पेंट उड़ गया। ऐसे ही हाल त्रिपरासुर की मूर्ति में उजागर होने लगा। मार्कण्डेय की मूर्ति के पिण्डी में पेंट निकल गया। दशानन के ऊपर पहाड़ का भी रंग झड़ गया। इसके अलावा माँ सरस्वती की मूर्ति से भी मटेरियल झडने लगा है। हालात यह है कि एक वर्ष के भीतर ही मूर्तियां में वापस पेंट होने का काम चालू हो गया है। जैसे अभी समुद्र मंथन में ताजा-ताजा पेंट हुआ है। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार की सीमा का अंदाजा इसी से लग सकता है कि कार्य आदेश क्रमांक 218 दिनांक 7.03.2019 के बिल क्रमांक 31 एमबी के पृष्ठ क्रमांक 9 पर फाईबर और प्लास्टिक के कार्य के 9 फीट के लिये 2.97 लाख रुपये, 10 फीट के लिये 4.67 लाख रुपये, 11 फीट के लिये 8.5 लाख रुपये एवं 15 फीट के लिये 10.2 लाख रुपये का भुगतान ठेकेदार को दिया गया। वैसे ही महाकाल के कार्य आदेश क्रमांक 218 दिनांक 7.03.2019 के बिल क्रमांक 31 की एमबी के पृष्ठ क्रमांक 13 पर 4 फीट हाईट के लिये 3.4 लाख, 12 फीट के लिये 17 लाख का भुगतान किया गया। इसके साथ ही एमबी के पृष्ठ क्रमांक 23 पर समुद्र मंथन की मूर्ति का बिल 1.82 करोड़ का भुगतान संबंधित ठेकेदार को दिया गया। जबकि इसी ठेकेदार ने सिंधी समाज के द्वारा बनवाये गये सेम मटेरियल और क्वालिटी 25 फीट ऊंची भगवान श्रीझूलेलाल की मूर्ति के लिये 4.11 लाख का भुगतान किया गया।

प्राधिकरण को सुपर विजन चार्ज के नाम पर का भुगतान कराया गया। इस अनियमितता को कलेक्टर के संज्ञान में लाया गया, किंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया जबकि नंदीहाल के विकास कार्य में उज्जैन विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-

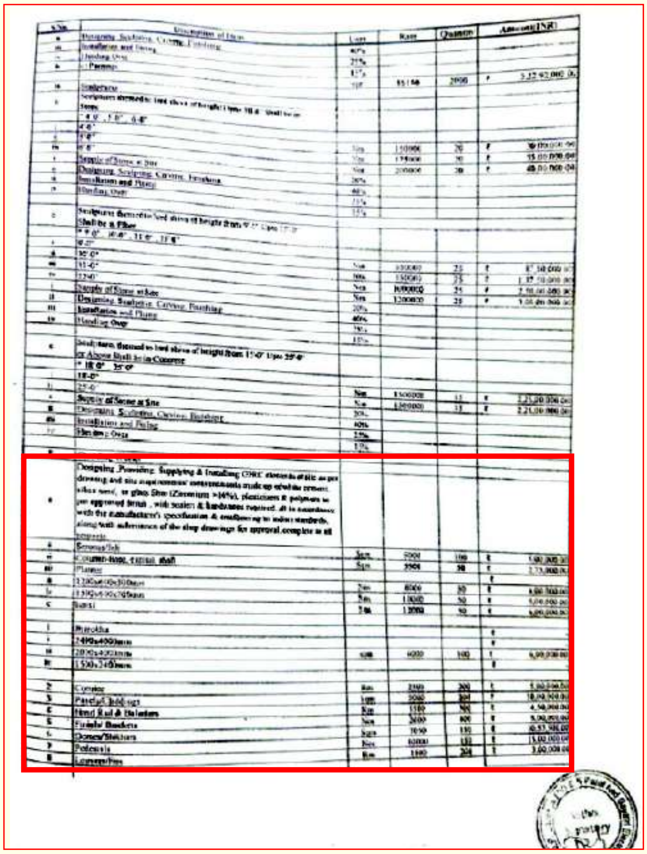

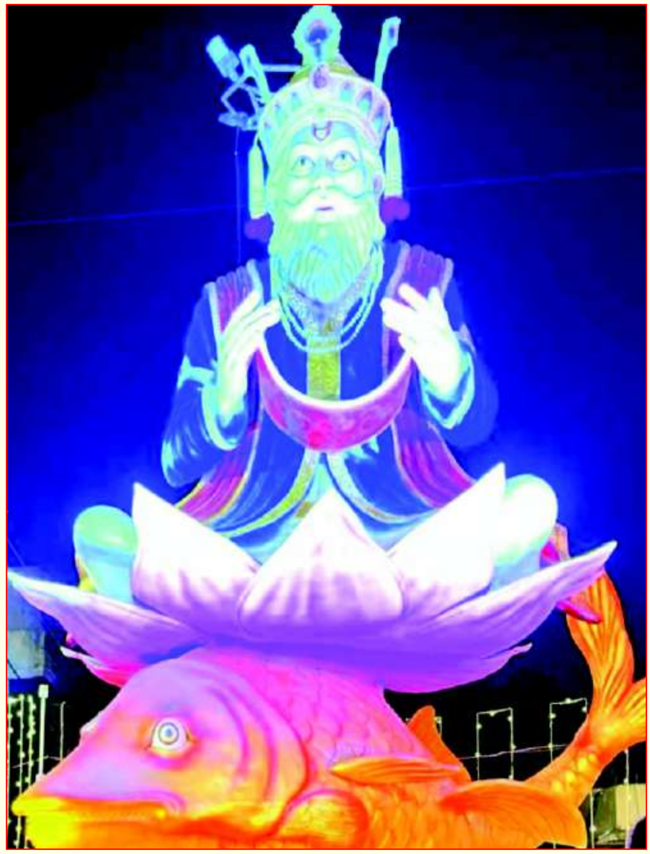

यह मूर्ति है श्री झूलेलाल भगवान की। उज्जैन में स्थापित यह मूर्ति उसी ठेकेदार ने बनाई है, जिस ठेकेदार ने महाकाल लोक में मूर्तियां बनाई है, लेकिन दिलचस्प है कि 25 फीट ऊंची झूलेलाल भगवान की मूर्ति के लिए सिंधी समाज ने 4.11 लाख का भुगतान किया। वहीं महाकाल लोक में सेम मटेरियल, सेम साईज की मूर्तियों के लिए ठेकेदार को कई गुना ज्यादा भुगतान किया गया है।

12-2012 के प्रस्ताव व ठहराव क्रमांक 4 के अनुसार किये गये कार्य का पर्यवेक्षण शुल्क नहीं लिया गया है। निविदा में पेटी कॉन्ट्रेक्टर (सब लेटिंग) का कोई प्रावधान नही था। उसके बाद भी पेटी ठेकेदारों से कार्य कराया गया। निविदा जानबूझकर सूक्ष्मता नही बनाई गई ताकि उसके प्रावधानों का फायदा उठाकर पैसा खाया जा सके। महाकाल लोक के आर्किटेक्ट हेतु

आईसोलेटर खरीदी घोटाला

500 प्रतिशत मंहगा करके खरीदा गया आईसोलेटर

महाकाल लोक के भ्रष्टाचार के लिये कैसे महाखेला रचा गया वह इस बात से साबित होता है जैसे कि विद्युत कार्य हेतु क्रमांक 6वें पर 33 किलो वॉट वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (VCB) ऑईसोलेटर त्रिवेणी म्युजियम हेतु खरीदने की प्रक्रिया में रिवाईड बिल ऑफ क्वांटिटी में 75 लाख का भुगतान ठेकेदार को किया गया। जबकि बाजार मूल्य में आईसोलेटर 10,3000 रूपये में उपलब्ध है और इंस्टालेशन और अन्य के साथ ज्यादा से ज्यादा 15 लाख का बांडेड वीसीबी उपलब्ध है। इसे कई गुना बढ़ाकर रेट दिये गये और ठेकेदार को भुगतान किया गया। आईसोलेटर तो सिर्फ एक उदाहरण भर है। लगभग 500 पन्नों की मेजरमेंट बुक/बीओक्यू के हर बिल पर सामान बाजार मूल्य से कई गुना मंहगा कर खरीदा गया। भ्रष्टाचार का पैमाना इतना बढ़ा है कि इसके ऊपर अगर 500 पन्नों के किताब भी लिखी जाये तो वह कम पड़ेगी। शिवराज सरकार के उज्जैन पदस्थ अधिकारियों ने भगवान के कार्यो में भी चोरी करने से गुरेज नही की। करीब-करीब प्रत्यक्ष तौर पर लगभग 300 करोड़ के बीच का यह घोटाला के पैसे किस-किस के पास पहुंचे मोदी जी को इसकी जांच जरुर करवानी चाहिए। बात और संदेहास्पद इसलिये भी नजर आती है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी जिसे लोकायुक्त ने नोटिस दिया है वह आशीष सिंह को भोपाल कलेक्टर के रूप में एलीवेट किया गया। सर्वोच्च पद पर बैठे अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। जिन मंत्रियों को महाकाल लोक का कार्य सौंपा गया उनको भी इस भ्रष्टाचारी हलवे का भाग अवश्य मिला होगा। खैर यह पूरा खेल बिना राजनीतिक संरक्षण के मुमकिन नहीं है।

5	Supply, Installation, Testing and Commissioning 11KV, 500 KVA, Outdoor Package / compact Sub-Station (in compliance IEC 62271-202) shall be consisting of following :as per tender	Nos	1	29,00,000.00	29,00,000.00
6	33KV VCB 3 Isolator (New item required for Triveni Museum Supply)	Nos	1	75,00,000.00	75,00,000.00
7	Supply,installation,testing and commissioning of outdoor type feeder pillar panels suitable for AC 440v, 50HZ supply, fabricated with 14 gauge galvanised steel sheet duly pre-treated and pure polyester thick powder coated and pure polyester thick powder coated 80 micron thickness using siemens grey colour shade no.RAL-7032/any other colour shade no.RAL-7032/Any other colour if required by cubical formation, compartmentalised in form with front openable doors The door shall be provided with concealed hinges and with brasing wherever required to avoid deformation and shall be earthed. All the door shall have heavy duty door locks, and shall be sealed with neoprene gaskets. the feeder pillar shall be IP 55, outdoor type weather, dust and vermin proof having canopy type tapered roof self-standing type as per approved GA Diagram. Panels shall have lifting hooks and base channel of size 50x40x6 mm				
	TYPE- A	Nos	4	1,12,000.00	4,48,000.00
	Rating of incomer MCCB TPN 63A, 25 KA				
	(Adjustable thermal O/L with ics=100%icu).				
	Outgoings 32A 25KA SP MCCB 12Nos. & 25A				
	25KA SP MCCB 18Nos.				
	Note: The width of feeder pillar should be as				
	minimum as possible, preferably not more than				
	800mm.				
	TYPE -B	Nos	4	1,65,000.00	6,60,000.00
	Rating of incomer MCCB TPN 100A, 25 KA				

Krishna Murari Sharma
Assistant Architect
PDMC, Ujjain Smart City Limited

Annexure – A (Commercial Offer)

Sr. No.	Description of Items	Unit	Qty.	Unit Rate	Total Amount (Without Taxes)	Taxes (GST%)	Disc. (%)	Total Price (With Taxes)
1	33 KV VCB , 1250 Amps ,31.5kA / 3 Sec , Metal Clad, outdoor Type ,1 Set of 1 ICOG VCB Panel (as per attached BOM) Make-ABB(System House)	SET	1	850000	850000	18	0.00	1003000
	Sub Total							INR 850000
	Total Tax							INR 153000
	Total Discount							INR 0
	Total Amount							INR 1003000
	Amount In Words : INR Ten Lakh Three Thousand only							

महाभ्रष्टाचार के खेला में 12 से 15 लाख का आयसोलेटर 75000 लाख में खरीदा गया।

नितिन श्रीमाल जो कि इंदौर से हैं उनको दिया गया इसके लिये प्रतिदिन का 65 हजार का भुगतान सरकार द्वारा दिया गया। सरकार द्वारा आकीर्टेक्ट हेतु कोई विज्ञप्ति जारी नही की गई थी। इसके अलावा संगीता बैस की नियुक्ति मूर्तियों की डिजाईन

हेतु की गई जिसके लिये उनका भी सरकार ने प्रतिदिन 22 हजार रुपये भुगतान किया। इनके लिये भी सरकार द्वारा कोई भी विज्ञप्ति जारी नही की गई। दरअसल महाकाल लोक के निर्माण की जिम्मेदारी कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के

जगत विजन ने पिछले एक महीने से महाकाल लोक में हुये भ्रष्टाचार की सघन पड़ताल कर रहा है। मूर्तियां तेज हवा से खण्डित होने से पहले ही उज्जैन में उनकी सूक्ष्मता से जायजा लिया गया जिसमें मूर्ति के विकृत्ती साफ दिखाई दे रही है।

ऊपर थी। निर्माण स्थल पर सामान की जांच हेतु एक लेबोरेट्री स्थापित करनी थी पर कोई लेबोरेट्री स्थापित नही कराई गई। मूर्तियां ग्लास, फायबर, कांक्रीट, पत्थर की बननी थी। जैसा कि अयोध्या स्थित भगवान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में बन रहा है पर

कम्प्यूटर खरीदी घोटाला

90 हजार का कम्प्यूटर, 1.5 लाख का भुगतान

महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का पैमाना इतना बड़ा है कि बीओक्यू/मेजरमेंट बुक में कोई भी बिल क्वांटिटी पर पड़ताल करने पर घपले की बात सामने आ रही है। जैसा कि पृष्ठ क्रमांक 70 में श्रंखला 13 आईसीटी कम्पोनेंट क्रमांक 06 पर कम्प्यूटर खरीदे जाने का उल्लेख किया गया है, जिसमें 06 कम्प्यूटर 1.5 लाख प्रति कम्प्यूटर की दर से 9 लाख का कुल एस्टीमेट बनाया गया। इसमें आई-7 कम्प्यूटर 160 जीबी रेम, 2 जीबी ग्राफिक कार्ड, 128 एसएसडी, 1 टीबी हार्डडिस्क, कीबोर्ड, 3 बटन माउस और वीडियो मॉनीटरिंग जॉयेस्टिक की विशेषता वाला कम्प्यूटर का 1.5 लाख का एस्टीमेट बनाया गया। जगत विजन द्वारा लोकल वेंडर से एस्टीमेट लेने पर उक्त कम्प्यूटर 78,900 साथ में सीसीटीवी जॉयेस्टिक 10-12 हजार की कीमत में उपलब्ध हो रहा है। इसका मतलब प्रत्येक कम्प्यूटर में सरकार द्वारा लगभग 50-60 हजार रूपये का भ्रष्टाचार किये गये। ऐसे ही बहुत सारे छोटे-छोटे भ्रष्टाचार करीब-करीब हर बिल में किया गया है। जाकि 20 प्रतिशत से लेकर मूल वस्तु के कई गुना तक हैं।

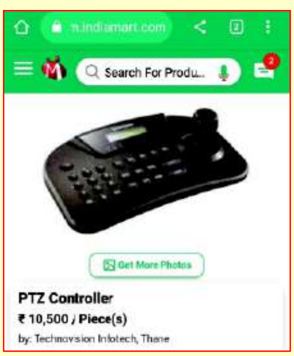

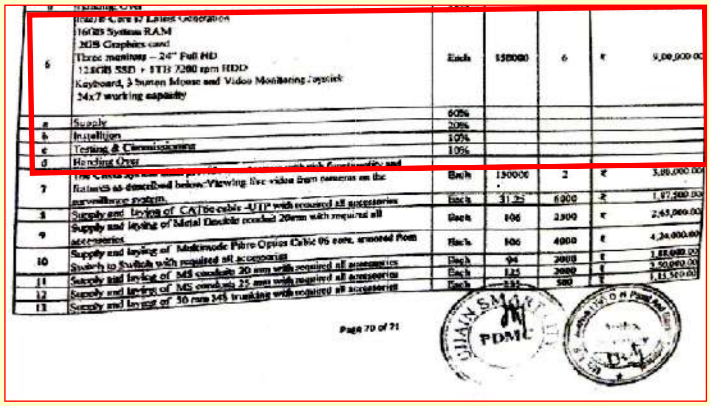

6	Intel i7 Core i7 Latest Generation 16GB System RAM 2GB Graphics card Three monitors – 24" Full HD 128GB SSD + 1TB 7200 rpm HDD Keyboard, 3 Button Mouse and Video Monitoring Joystick 24x7 working capacity	Each	150000	6	₹	9,00,000.00
a	Supply	60%				
b	Installation	20%				
c	Testing & Commissioning	10%				
d	Handing Over	10%				
7	[illegible] with rich functionality and features as described below: Viewing live video from cameras on the surveillance system.	Each	150000	2	₹	3,00,000.00
8	Supply and laying of CAT6e cable -UTP with required all accessories	Each	31.25	6000	₹	1,87,500.00
9	Supply and laying of Metal Double conduit 20mm with required all accessories	Each	106	2500	₹	2,65,000.00
10	Supply and laying of Multimode Fibre Optics Cable 06 core, armored from Switch to Switch with required all accessories	Each	106	4000	₹	4,24,000.00
11	Supply and laying of MS conduits 20 mm with required all accessories	Each	94	2000	₹	1,88,000.00
12	Supply and laying of MS conduits 25 mm with required all accessories	Each	125	2000	₹	3,50,000.00
13	Supply and laying of 30 mm MS trunking with required all accessories	Each	[illegible]	500	₹	1,13,500.00

Page 70 of 71

UJJAIN SMART PDMC

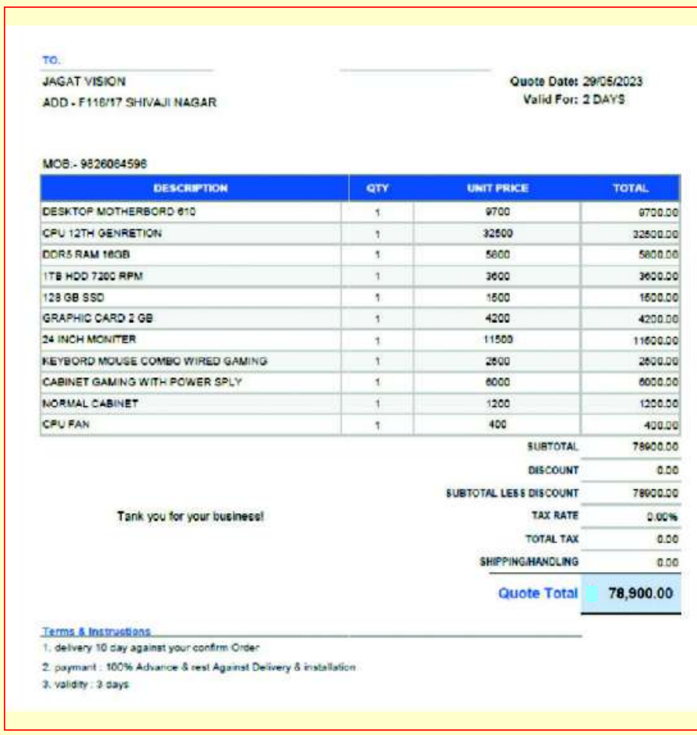

TO.
JAGAT VISION
ADD - F116/17 SHIVAJI NAGAR

Quote Date: 29/05/2023
Valid For: 2 DAYS

MOB:- 9826064596

DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
DESKTOP MOTHERBORD 610	1	9700	9700.00
CPU 12TH GENRETION	1	32500	32500.00
DDR5 RAM 16GB	1	5800	5800.00
1TB HDD 7200 RPM	1	3600	3600.00
128 GB SSD	1	1500	1500.00
GRAPHIC CARD 2 GB	1	4200	4200.00
24 INCH MONITER	1	11500	11500.00
KEYBORD MOUSE COMBO WIRED GAMING	1	2500	2500.00
CABINET GAMING WITH POWER SPLY	1	6000	6000.00
NORMAL CABINET	1	1200	1200.00
CPU FAN	1	400	400.00
		SUBTOTAL	78900.00
		DISCOUNT	0.00
		SUBTOTAL LESS DISCOUNT	78900.00
		TAX RATE	0.00%
		TOTAL TAX	0.00
		SHIPPING/HANDLING	0.00
		Quote Total	78,900.00

Tank you for your business!

Terms & Instructions
1. delivery 10 day against your confirm Order
2. paymant : 100% Advance & rest Against Delivery & installation
3. validity : 3 days

इसके विपरीत सस्ता और कम टिकाऊ प्लास्टिक फायबर से इसका निर्माण किया गया। मध्यप्रदेश के जनवासियों की महाकाल के प्रति आस्था का भी नही सोचा गया। इसी कड़ी में 33 किलोवॉट का ऑईसोलेटर जो कि बाजार में 12 से 15 लाख रुपये तक मिल जाता है पर सरकार ने उसके लिये भी 75 लाख रुपये का भुगतान किया। एक बड़ा घोटाला मूर्तियों में

महाकाल लोक हुआ तहस-नहस कागज की तरह उड़ गई मूर्तियां

एक्सपर्ट ने माना कमजोर निर्माण के कारण धराशायी हुईं मूर्तियां

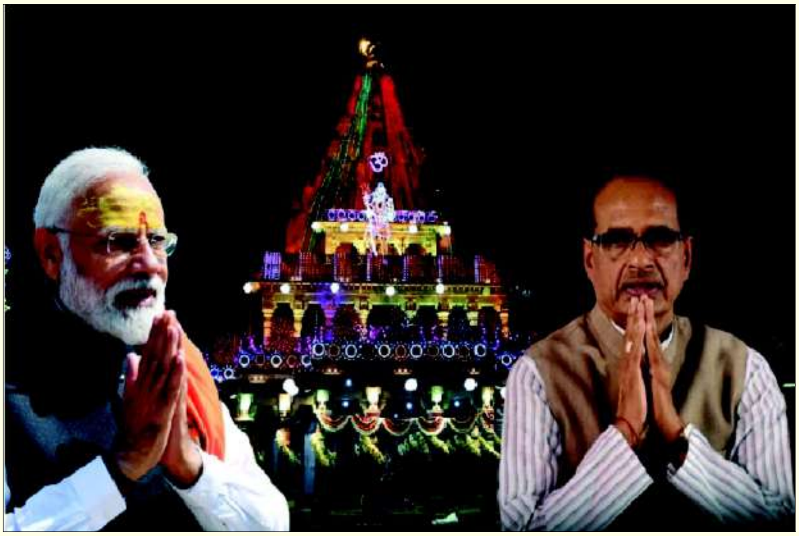

महाकाल लोक के निर्माण में लगभग 05 साल का वक्त लगा। पांच साल की इस मेहनत पर केवल 15 मिनट की हवा हावी हो गई। लगभग 30 किमी घंटे की स्पीड से चली हवा में ही महाकाल लोक में लगी मूर्तियां उखड़ गई। विपक्ष ने भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के आरोप लगाए। लेकिन सरकार और प्रशासन ने इसे प्राकृतिक घटना बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। इसके साथ ही एक्सपर्ट ने माना है कि मूर्तियों के कमजोर निर्माण के कारण धराशायी हुई हैं। इन मूर्तियों का निर्माण पत्थर का होना चाहिए था। हम भी मूर्तियों को देखकर कह सकते हैं कि धराशायी हुईं महाकाल लोक की 06 मूर्तियां अंदर से खोखली थीं। मूर्तियों का बेस ही बहुत कमजोर था। जबकि, इसे बनाने वाली एमपी बावरिया कंपनी ने इनकी लाइफ 10 साल बताई थी। तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने तो इनका जीवन 100 वर्षो का बताया था। महाकाल लोक के निर्माण के समय बताया गया था कि लोक में जो मूर्तियां लगाई जायेगी वह पत्थर की होगी और इनकी उम्र 100 साल होगी। अब उज्जैन के कलेक्टर कुमार परषोत्तम मामले पर लीपापोती करते हुए कहते हैं कि पत्थर की मूर्तियों को बनाने में समय लगता है और भविष्य में पत्थर की मूर्तियां लगायी जायेगी। अभी प्लास्टिक की मूर्तियां ही लगायी जायेगी। जांच के विषय में उनका कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि तेज आंधी के कारण मूर्तियां गिरी हैं। इन्हें पुनः उन्हीं स्थानों पर लगाया जायेगा। आपको बता दें कि पूरे महाकाल लोक में करीब 136 मूर्तियां लगाई गई हैं। करोड़ो की लागत में मूर्तियां बनाई गई थी और औसतन एक मूर्ति बनाने में 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। महाकाल लोक बनने की शुरुआत 2018 में हुई। फ्लोर का काम शुरू होने के बाद सबसे पहले सप्तऋषियों की मूर्तियां स्थापित की गई थीं। हाल ही में चली हवा में सप्तऋषि की 07 में से 06 मूर्तियां पेडस्टल से नीचे गिर गईं। स्थापित मूर्तियों में से किसी का धड़ गिर गया तो किसी का हाथ टूट गया। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया था, उस समय भी मूर्तियों की मजबूती को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। इससे पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी ही बारीकी से महाकाल लोक का निरीक्षण किया था और इसकी भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता का काफी बखान किया था। उनकी बातों को सुनकर तो यहीं लगता था कि महाकाल लोक में जो निर्माण हुआ है

आया। चूंकि महाकाल लोक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सरकार द्वारा इसका थर्ड पार्टी ऑडिट नही कराया गया और करायेंगे भी कैसे वरना सरकार के इस महा भ्रष्टाचार का खेल सबके सामने आ जायेगा। चूंकि महाकाल लोक प्रधानमंत्री का 2024 का मुख्य मुद्दा है। ऐसे में शिवराज सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को भी अंधेरे में रखकर जनता के साथ धोखा

वह कई दशकों तक खत्म नहीं होगा। महाकाल लोक के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक ने शिकायत में ठेकेदार मनोज भाई पुरुषोत्तम भाई बाबरिया को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाने के लिए (शेड्यूल ऑफ रेट) की दरें और आइटम को बदलने का आरोप लगाया गया था। टेंडर में न्यूनतम निविदाकार (टेंडरर) होने के बाद भी एमपी बाबरिया को काम दिया। स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंशुल गुप्ता ने ठेकेदार को लगभग 01

30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा में ही उखड़ गई मूर्तियां

करोड़ का आर्थिक लाभ पहुंचाया है। टेंडर अनुसार जस्ती लोहा शीट लगानी थी, जिस पर 22 लाख का खर्च होना था। ठेकेदार ने इसकी जगह पॉली कार्बोनेट की शीट लगाई है। यह अतिरिक्त आइटम जोड़ा गया। पॉली कार्बोनेट शीट की एसओआर दर (शेड्यूल ऑफ रेट) 3105 रुपए प्रति वर्गमीटर है, जबकि बाजार दर 808 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इस प्रकार ठेकेदार को लाखों का अनुचित फायदा मिला है। ऐसे ही अन्य आइटम बदले गए। कुल टेंडर 3.62 करोड़ रुपए का था, जो करीब सवा करोड़ तक बढ़ गया। सोलर निर्माण कार्य में ड्रॉइंग और डिजाइन चेंज किया गया है। इधर, पूर्व सीएम कमलनाथ ने महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कांग्रेस के 07 नेताओं की टीम बनाई है। उन्होंने सीएम शिवराज से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बता दें कि महाकाल लोक का निर्माण करने वाली कंपनी गुजरात की है और 2006 में इस कंपनी ने अपना कार्यालय इंदौर में खोला था। मूर्तियों का बेस बेहद कमजोर था। नीचे की ओर इतनी जगह छोड़ दी गई कि इससे आसानी से हवा-पानी अंदर जा सकता था। 10 से 25 फीट ऊंची मूर्तियों को फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनाया गया था। मजबूती देने के लिए अंदर सरिए लगाने होते हैं, लेकिन मूर्तियां खोखली थीं। मूर्तियों की बनावट इस तरह की नहीं थी कि वे 30 से 50 किमी घंटे की स्पीड से चलने वाली हवा झेल सकें। मूर्तियां हवा का प्रेशर झेल नहीं सकीं।

मूर्तियों के जानकर ने बताया कि फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी मूर्ति का वजन हल्का होता है। जब एफआरपी से बनी मूर्तियों को ऊंची जगह पर लगाया जाता है, तब मजबूती देने के लिए एक केमिकल डाला जाता है, जो अंदर जाते ही फोम के रूप में होते हुए मजबूत हो जाता है। महाकाल लोक की मूर्ति अंदर से खोखली है। इस कारण हवा का प्रेशर नहीं झेल पाई। ऐसी मूर्तियों को लोहे की प्लेट लगाकर लोहे के सेक्शन पर कसना चाहिए था। मूर्तियों को डिजाइन करने वाले स्मार्ट सिटी के साथ काम कर रहे कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि प्लान में पहले से ही था कि एफआरपी की मूर्तियों को अंदर से खोखला बनाकर अंदर स्टील या लोहे की रॉड से मजबूती दी जाएगी। संभवतः मूर्तियों के आधार में मजबूती नहीं होने के कारण ही मूर्ति गिरी हैं। मूर्तियों की मजबूती के लिए इनमें केमिकल डालकर इन्हें ठोस किया जा सकता था। इससे इनकी उम्र भी कई गुना बढ़ जाती। हालांकि, इस प्रोसेस में मूर्तियां कई गुना महंगी बनतीं और मूर्ति बनाने का बजट भी बढ़ जाता। शायद इसलिए महाकाल लोक में प्लास्टिक की मूर्तियां लगाई गई है।

किया गया। इस महाकाल लोक में ऐसे बहुत सारे काम हैं, जो कि बिना निविदा के करा दिये गये। प्रधानमंत्री मोदी को महाकाल लोक के उद्घाटन के लिये बुलाया गया और सरकार की कमियां न उजागर हो जाये इसके लिये करीब-करीब 100 करोड़ रुपये का खर्चा अलग से किया गया। जिसका भुगतान भोपाल से किया गया। प्रधानमंत्री के डोम के लिये 16

लोकायुक्त ने माना आशीष सिंह हैं महाकाल लोक ने मुख्य साजिशकर्ता !

विधायक महेश परमार ने पहले की थी निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता की लोकायुक्त में शिकायत

उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा निविदा विज्ञप्ति क्रमांक USCL/75 दिनांक 06.02.2021 के द्वारा Construtioal of open Surface Parking Shed with Solar PV System, Tender ID:- 2021 UAD--127805 रुपये 3,62,68,055- का टेण्डर निकाला गया था। इस टेण्डर में न्यूनतम निविदाकार ठेकेदार एम.पी. बाबरिया द्वारा 17.67 प्रतिशत यूएडीडी एक्सज़ोर से कम पर उक्त टेण्डर लिया था। उज्जैन स्मार्ट सिटी के कार्यपालक निदेशक अंशुल गुप्ता द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर ठेकेदार एम.पी. बाबरिया को लगभग एक करोड़ रूपये का आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। जिसकी बिंदुवार जांच की जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि अंशुल गुप्ता द्वारा किस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग कर ठेकेदार से मिलकर भ्रष्टाचार किया है तथा केन्द्र सरकार की महती योजना को चौपट किया है। इस संबंध में विधायक महेश

करोड़, भीड़ जुटाने के लिये 6.5 करोड़ रुपये खर्च किये गये। प्रधानमंत्री का उज्जैन से इंदौर तक के मार्ग में खम्बे और रातोंरात लाईट लगा दी गई एवं पौधे लगाये गये पर उनके जाते ही सब एकदम से गायब हो गया।

प्रदेश में कई और लोक घोटाले, पैसों के लिये तो नही कर रही शिवराज सरकार

दरअसल महाकाल लोक की आड़ में

आशीष सिंह, तत्कालीन कलेक्टर, उज्जैन

क्षितिज सिंघल, तत्कालीन ईडी सिटी

अंशुल गुप्ता, तत्कालीन ननि आयुक्त, उज्जैन

परमार ने लोकायुक्त को पत्र लिखकर महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की बिंदुवार जानकारियां दी। शक के दायरे में निम्न बिंदु-

■ उपरोक्त कार्य की निविदा में आयटम क्रमांक 1 लगायत 10 एवं इलेक्ट्रिक आयटम 2 लगायत 20 सभी आयटम एडीडी एससीआर पर लिये गये हैं जबकि आयटम नम्बर 11 जो कि जी.आई. शीट का आयटम है, को पीडब्ल्यूडी एसओआर 2020 आयटम नंबर 12:15 से लिया गया है।

■ जबकि यूएडीडी एसओआर जी.आई. शीट की दर आयटम नम्बर 12.1.3 एवं पेज नम्बर पर रू. 572/- प्रति स्येर मीटर है। वहीं पीडब्ल्यूडी एसओआर में यह दर रूपये 652/- प्रति स्केयर मीटर की है।

■ अंशुल गुप्ता द्वारा अत्यंत षडयंत्रपूर्वक सिर्फ जी.आई. शीट की आयटम को ही पीडब्ल्यूडी एसओआर पर लिया गया है क्योंकि यदि यह कार्य एमपी बावरिया को नहीं मिलता तो इस कार्य में जीआई शीट ही लगना थी किन्तु जब उनके चहते एमपी बावरिया ने कार्य 17.67 प्रतिशत एसओआर से कम पर ले लिया तो उनके द्वारा अपने अधिनस्थों पर पद का दुरूपयोग करते हुए दबाव डालकर टेण्डर में शामिल जीआई सीट आयटम की परिवर्तित करते हुए पोलीकार्बोनेट शीट का उपयोग किये जाने के आदेश एमपी बावरिया को दिये गये एवं इनके द्वारा लगभग 100 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ ठेकेदार को दिया गया है। ठेकेदार को टेण्डर अनुसार जीआई शीट लगानी थी जिस पर कुल व्यय रुपये 2,27,4,490- का होना था। एमपी बावरिया द्वारा जीआई शीट की स्थान पर जो पोली कार्बोनेट की लगाई गई है और दर 3105/- रूपये प्रति स्वेयर मीटर है। इस प्रकार कुल रुपये 1,20,34,980/- रूपये का नये आयटम जोड़ने पर व्यय किया गया। स्पष्ट है कि ठेकेदार को अतिरिक्त

शिवराज सरकार को यह समझ में आया कि ऐसे प्रोजेक्ट से सरकार और उससे जुड़े लोगों की दोनों हाथ घी में डूबे रहते हैं। एक तरफ लोगों का मन आस्था की तरफ सरकार का आकर्षण पैदा होता है और दूसरी तरफ भारी भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाता है। लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों के महाकाल लोक के भ्रष्टाचार से आये पैसों

आशीष पाठक, सीईओ, स्मार्ट सिटी, उज्जैन

इनको दिए नोटिस- स्मार्ट सिटी के तत्कालीन कार्यपालक निदेशक क्षितिज सिंघल और तत्कालीन नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता शामिल हैं। इनके अलावा उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मनोनीत निदेशक सोजन सिंह रावत और दीपक रतनावत, स्वतंत्र निदेशक श्रीनिवास नरसिंह राव पांडुरंगी, स्मार्ट सिटी उज्जैन के सीईओ आशीष पाठक, तत्कालीन सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान, मुख्य वित्तीय अधिकारी जुवान सिंह तोमर, तत्कालीन अधीक्षण यंत्री धर्मेंद्र वर्मा, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री फरीदुद्दीन कुरैशी, सहायक यंत्री कमल सक्सेना, उपयंत्री आकाश सिंह, पीडीएमसी उज्जैन स्मार्ट सिटी के टीम लीडर संजय शाक्या और जूनियर इंजीनियर तरुण सोनी हैं।

भुगतान करने हेतु आयटम बदल कर किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि जीआई शीट की एसओआर दर बाजार दर से काफी अधिक है जिसके कारण से ठेकेदार को लगभग रुपये 14,57,376/- का नुकसान होता। इसी प्रकार पोली कार्बोनेट शीट का एसओआर दर 3105/- रूपये प्रति स्केयर मीटर है जबकि बाजार दर 808/- रूपये प्रति स्केयर मीटर है। इस प्रकार से ठेकेदार को कुल रूपये 91,62,864/- रूपये का अनुचित लाभ दिया गया है। इसके साथ ही अन्य आयटमों भी ठेकदार की इच्छानुसार आयटम एवं अन्य परिवर्तन करके लाभ दिया गया है।

■ इस प्रकार टेण्डर लागत 3.62 करोड़ की 33 प्रतिशत से अधिक 1.20 करोड़ लागत का आयटम बदला गया है, जो वर्क मेन्युक्ल एवं UADD की गाईडलाईन के विपरीत है। इसके अलावा भी उक्त सोलर निर्माण कार्य में ड्राइंग डिजाईन परिवर्तन करके भी ठेकेदार को अन्य आयटम में भी लाभ दिया गया है। इस टेण्डर में जानबूझकर जीआई शीट का आयटम रेट पीडब्ल्यूडी एसओआर 2020 से लिया गया जबकि उज्जैन स्मार्ट सिटी उज्धैन द्वारा सभी निर्माण कार्य के टेण्डर यूएडीडी एसओआर निकाले जाते हैं। उक्त जीआई शीट का आयटम भी यूएडीडी एसओआर में है। यह आयटम बदलने का षडयंत्र टेण्डर जारी होने के पूर्व से ही निर्धारित था। इसी कारण जीआई सीट का आयटम पीडब्ल्यूडी एसओआर से लेकर टेण्डर निकाला गया।

सम्पूर्ण कार्य में निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच की जाये-

■ टेण्डर में सिविल निर्माण कार्य के सभी आयटम जैसे खुदाई, लोहा, कांक्रीट, मुरम आदि यूएडीडी एसओआर से लिये हैं और जीआई शीट का आयटम पीडब्ल्यूडी एसओआर से लिया है जबकि जीआई शीट का आयटम यूएडीडी एसओआर के हैं। इस बिन्दु की जाँच होना चाहिए।

के कारण ही प्रदेश में 4-5 ऐसे लोक की घोषणा कर दी। भगवान महाकाल के नाम पर भी चोरी करने में इनको जरा भी शर्म महसूस नही होती जबकि भाजपा पार्टी का मुख्य बेस ही हिन्दू और हिन्दुत्व है। भ्रष्टाचार के ईनाम स्वरूप ही तब वहां के तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह के ऊपर लोकायुक्त ने महाकाल लोक निर्माण को लेकर मामला दर्ज किया पर इस भ्रष्टाचार

महेश परमार
विधायक, तराना
विधानसभा क्षेत्र क्र. 214

विधायक विश्रामगृह नवीन परिसर
खण्ड-ब, क्र. 8, भोपाल (म.प्र.)
14, बसीखा क्वार्टर, धनधना, कोठी रोड,
उज्जैन (म.प्र.)

M. 98260-42177

क्र.

दिनांक 27-05-22

प्रेस नोट

विधायक महेश परमार ने खोली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चल रही आर्थिक धांधलियों की पोल।

उक्त जानकारी विधायक श्री परमार के निज सहायक द्वारा दी गयी।

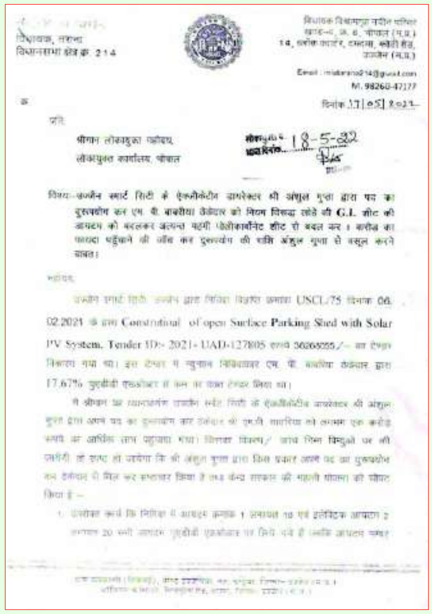

विधायक, तराना
विधानसभा क्षेत्र क्र. 214

M. 98260-42177

प्रति,

श्रीमान लोकायुक्त महोदय
लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल

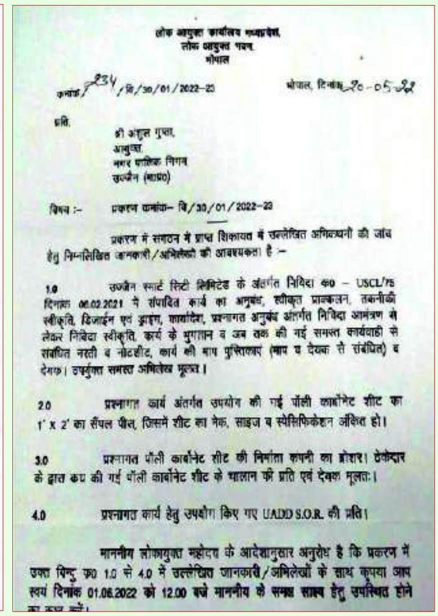

लोक आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
लोक आयुक्त भवन
भोपाल

क्रमांक/234/वि/30/01/2022-23 भोपाल, दिनांक 20-05-22

प्रति,

श्री अंशुल गुप्ता,
आयुक्त,
नगर पालिक निगम
उज्जैन (म0प्र0)

विषय :- प्रकरण क्रमांक- वि/30/01/2022-23

प्रकरण में संगठन में प्राप्त शिकायत में उल्लेखित अभिकथनों की जांच हेतु निम्नलिखित जानकारी/अभिलेखों की आवश्यकता है :-

1.0 उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत निविदा क्र0 - USCL/75 दिनांक 06.02.2021 में संपादित कार्य का अनुबंध, स्वीकृत प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, डिजाईन एवं ड्राइंग, कार्यादेश, प्रश्नागत अनुबंध अंतर्गत निविदा आमंत्रण से लेकर निविदा स्वीकृति, कार्य के भुगतान व अब तक की गई समस्त कार्यवाही से संबंधित नस्ती व नोटशीट, कार्य की माप पुस्तिकाएं (माप व देयक से संबंधित) व देयक। उपर्युक्त समस्त अभिलेख मूलतः।

2.0 प्रश्नागत कार्य अंतर्गत उपयोग की गई पॉली कार्बोनेट शीट का 1' x 2' का सैंपल पीस, जिसमें शीट का मेक, साइज व स्पेसिफिकेशन अंकित हो।

3.0 प्रश्नागत पॉली कार्बोनेट शीट की निर्माता कंपनी का ब्रोशर। ठेकेदार के द्वारा क्रय की गई पॉली कार्बोनेट शीट के चालान की प्रति एवं देयक मूलतः।

4.0 प्रश्नागत कार्य हेतु उपयोग किए गए UADD S.O.R. की प्रति।

माननीय लोकायुक्त महोदय के आदेशानुसार अनुरोध है कि प्रकरण में उक्त बिन्दु क्र0 1.0 से 4.0 में उल्लेखित जानकारी/अभिलेखों के साथ कृपया आप स्वयं दिनांक 01.06.2022 को 12.00 बजे माननीय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित होने

विधायक महेश परमार द्वारा लोकायुक्त को की गई शिकायत और लोकायुक्त का अभियुक्तो को नोटिस।

■ किस तकनीकी आधार एवं आवश्यकता के आधार पर जीआई शीट की जगह पोलीकार्बोन शीट लगाई गई है।

■ किस नियम के तहत टेण्डर लागत के 33 प्रतिशत अधिक लागत का नया आयटम बदला गया।

■ उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा सभी कार्य की निविदा यूएडीडी एसओआर पर आमंत्रित की जाती हैं, फिर जीआई शीट का आयटम यूएडीडी एसओआर में होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी एसओआर के आयटम को क्यों लिया गया।

■ यह पूर्व नियोजित था कि पीडब्ल्यूडी एसओआर के जीआई शीट का आयटम टेण्डर में लेकर फिर टेण्डर के बाद पीडब्ल्यूडी एसओआर से जीआई शीट का आयटम पालीकार्बनेट से बदला जायेगा।

■ इस बात की भी जांच होना चाहिए कि इस टेण्डर में पूर्व से आइटम बदलने में ठेकेदार और अधिकारी दोनों की पहले से ही मिलीभगत थी। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इस हेराफरी को कर अंशुल गुप्ता द्वारा 40 लाख रुपये तथा ठेकेदार द्वारा 60 लाख रूपये आपस में बांटे हैं।

महाकाल लोक घोटाला : लोकायुक्त के शिकंजे में फंसे अधिकारी

लोकायुक्त संगठन को मिली शिकायत के अनुसार आरोप है कि अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके एक ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाया है। इस मामले में लोकायुक्त ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर चुका है और इसकी जांच चल रही है। श्री महाकाल लोक निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले की लोकायुक्त ने जांच तेज कर दी है।

के ईनाम स्वरूप आशीष सिंह को पहले मध्यप्रदेश रोड डव्लपमेंट कार्पोरेशन जैसे मलाईदार विभाग का प्रबंध संचालक बना गया उसके बाद उनको भोपाल कलेक्टर की पदस्थापना दे दी गई। देश में महाकाल लोक शायद पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां पर एंस्टोलेकशन के बाद हैण्डलिंग और कमिशनिंग के पैसे बांटे गये।

लोकायुक्त की तरफ से जारी नोटिस का जवाब देने दो आईएएस समेत पांच अधिकारी पहुंचे। उन्होंने लोकायुक्त से जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा था, हालांकि तत्कालीन उज्जैन कलेक्टर पेश नहीं हुए। लोकायुक्त ने जिन 15 अफसरों को नोटिस भेजा था, उनमें से 11 भोपाल में पेश हुए और अपना जवाब पेश किया। लोकायुक्त ने जिन अफसरों को नोटिस भेजा उनमें तीन आईएएस अफसर हैं।

सूत्रों के अनुसार लोकायुक्त के सामने आईएएस अफसर क्षितिज सिंघल, अंशुल गुप्ता समेत 11 अफसरों ने अपना जवाब पेश किया। लोकायुक्त संगठन को कांग्रेस विधायक महेश परमार ने शिकायत की थी। इसमें आरोप है कि अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाया है। इन पर महाकाल लोक के प्रथम फेज के निर्माण में गुणवत्ता की पार्किंग का निर्माण करने और ठेकेदार के गलत को बिना जांच के पास करने, लोहे की जीआई शीट के आइटम को पॉली कार्बोनेट शीट में बदलकर एक करोड़ का फायदा पहुंचाने, चहेतों को उपकृत करने के आरोप लगे हैं। लोकायुक्त संगठन ने उज्जैन कलेक्टर और स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष आशीष सिंह तत्कालीन आयुक्त अंशुल गुप्ता को नोटिस भेजा था। इसके अलावा उज्जैन स्मार्ट के निदेशक सोजन सिंह रावत, दीपक रत्नावत, स्वतंत्र निदेशक श्रीनिवास नरसिम्हा राव पांडुरंगी, मुख्य परिचालन अधिकारी आशीष पाठक, तत्कालीन मुख्य परिचालन अधिकारी जितेंद्र सिंह चौहान शामिल हैं। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया था।

मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बोला झूठ, क्या भूपेन्द्र सिंह भी भ्रष्टाचार में शामिल है?

महाकाल लोक में प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने वहां पर कथित भ्रष्टाचार की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने काँग्रेस पर भी आरोप लगाया कि अगर यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे लिख कर दीजिये। भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि महाकाल लोक में आंधी और बवंडर के कारण यह मूर्तियां टूटी हैं इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। भूपेन्द्र सिंह इस मामले में झूठ बोल रहे हैं। उनको प्रदेश के लोकायुक्त जो कि सरकार के अधीन कार्य करते हैं उन्होंने ने ही महाकाल लोक भ्रष्टाचार से संबंधित 15 व्यक्तियों को नोटिस देकर रखा है। इस मामले में भूपेन्द्र सिंह पत्र क्रमांक 234/वि/30/01/2022-23 दिनांक 20-05-2022 का अवलोकन करें जिसमें लोकायुक्त ने संबंधितों को नोटिस दिया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के लिये फाईल नम्बर 0036/ई/2023-24 जांच के लिये तकनीकी शाखा में नोटशीट गई है। इसका मतलब यह हुआ भूपेन्द्र सिंह जिस तरह वहां हुये भ्रष्टाचार को बचाने में लगे हुये हैं उसके लिये झूठ बोल रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि पूरे भ्रष्टाचार में उनकी की संलिप्तता जाहिर होती है क्योंकि जिस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ वह उस विभाग के मंत्री हैं।

दरअसल कई जगह ठेकेदार को पैमेंट देते समय 60 प्रतिशत मूल कीमत 20 प्रतिशत एंस्टोलेकशन के दिये गये। एंस्टोलेकशन के बाद 10 प्रतिशत हैण्डलिंग और 10 प्रतिशत कमिशनिंग का भुगतान क्यों दिया गया यह समझ से परे है।

महाकाल लोक की भीड़ की आड़ में एक सौ करोड़ की चोरी दबी

उज्जैन शहर के राजस्व अमला

महाकाल में आने वाले कथित वीआईपी में उलझे रहते हैं, जनता के काम ठप्प पड़े हुए है। सांसद, विधायकों, कांग्रेस, भाजपा का रोज का कोटा तय है। इनकी संख्या कम होने की आड़ में यहाँ के कुछ पण्डे, पुजारी, सुरक्षाकर्मी और यहाँ कार्यरत कर्मचारियों

कमलनाथ ने रखी थी महाकाल लोक निर्माण की नींव

महाकाल लोक निर्माण की सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने पांच साल पहले सहमति दी थी। उस समय मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। उस समय कमलनाथ सरकार ने इस योजना के लिए 300 करोड़ रूपए स्वीकृत किए थे। इसके बाद तय किया गया कि महाकाल मंदिर के पीछे रूद्रसागर को भी शामिल किया जाए। उस समय साल 2017 में इसके लिए 870 करोड़ रूपये मंजूर किए गए थे। इसके बाद महाकाल लोक का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, हालांकि कोरोना काल में प्रोजेक्ट की गति कम हुई लेकिन काम नहीं रूका। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भगवान महाकाल मंदिर विकास के लिये 300 करोड़ रुपये मंज़ूर कर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने, नंदी हॉल का विस्तार करने एवं महाकाल कॉरिडोर के विकास का संकल्प लिया। कांग्रेस का कहना है कि यह प्रोजेक्ट उसकी सरकार की देन है। 2019 में कांग्रेस की सरकार ने 300 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट के लिए रखे थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमने जो किया वह रिकॉर्ड पर है। यह सब चीजों का श्रेय लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल कॉरीडोर की कल्पना 2016 में सिहस्थ के समय करने की बात कह चुके हैं।

कमलनाथ सरकार ने बनाया ब्लू प्रिंट- 2018 में कमलनाथ सरकार ने अपनी तरफ से सारे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था। महाकाल कॉरीडोर कैसे बनेगा, यह ब्लू प्रिंट कमलनाथ सरकार ने जारी किया था। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में की गई थी। बैठक में महाकाल मंदिर विकास की 300 करोड़ की इस योजना का विस्तृत ब्यौरा महाकाल मंदिर के पुजारियों और मंत्रिमंडल के सदस्यों के सम्मुख रखा गया था। जिसमें फ्रंटियर यार्ड, नंदी हाल का विस्तार, महाकाल थीम पार्क, महाकाल कॉरिडोर, वर्केज लॉन पार्किंग आदि का विकास और निर्माण प्रथम चरण में प्रस्तावित किया गया था। महाकाल मंदिर के विकास को तीव्र गति से किये जाने के संदर्भ में मंत्रियों की एक त्रिस्तरीय समिति भी गठित की, जिसमें उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री सजन सिंह वर्मा, आध्यात्म विभाग के मंत्री पीसी शर्मा और नगरीय निकाय विभाग के मंत्री जयवर्धन सिंह को समिति का सदस्य बनाया गया था। 25 फरवरी, 2019 को प्रथम चरण के टेंडर इनवाईट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। महाकाल मंदिर के प्रथम चरण के विकास के लिए 07 मई 2019 को 97 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। कमलनाथ सरकार ने इसी प्रकार मप्र स्थित ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग मंदिर निर्माण के लिए भी 150 करोड़ रू का प्रावधान किया था। कमलनाथ सरकार समूचे मप्र के मंदिरों के विकास और विस्तार की व्यापक योजना पर काम कर रही थी और कमलनाथ सरकार मंदिर विधेयक 2019 लेकर आयी थी और कमलनाथ सरकार ने ज्योर्तिलिंग महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, रामपथ वन गमन के साथ ही श्रीलंका में माता सीता के मंदिर सहित समूचे मप्र के मंदिरों के विकास और विस्तार के साथ मंदिरों के पुजारियों के मानदेय के लिए एक व्यापक अग्रणी भूमिका का निर्वाहन किया था।

महाकाल लोक के भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच होना चाहिए- कमलनाथ का कहना है कि महाकाल लोक निर्माण की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये। इसके दोषी कोई भी हों, बख्शे नहीं जाने चाहिये। शिवराज सरकार में हर योजना, हर काम में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। चाहे वर्तमान में पोषण आहार का मामला हो, गरीबों को राशन का मामला हो, कारम बांध निर्माण का मामला हो या पूर्व के सिंहस्थ से लेकर पौधारोपण, व्यापमं, डंपर, ई-टेंडर व अन्य मामले हों।

पर पैसे ऐंठकर श्रद्धालुओं को लूट रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में गिनती के दौरान रुपये चुराने वाले, अवैध वसूली करने वाले, तांबा काण्ड इन सबके विरुद्ध महाकाल थाने में मंदिर प्रशासन ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था, आज तक किसी में

महाकाल लोक के भ्रष्टाचार का असली मास्टरमाइंड तत्कालीन उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह

उज्जैन के महाकाल लोक के प्रथम फेस का कार्य पूर्ण हो गया है और इसे आमजनों के लिए भी खोल दिया गया है। इस महाकाल लोक के निर्माण से लेकर इसके लोकार्पण तक में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण को लेकर सरकार और अफसर कठघरे में हैं। लोक के घटिया निर्माण और वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार का असली मास्टरमाइंड आशीष सिंह हैं क्योंकि लोक के पूरा कार्य उज्जैन के तत्कालीन कलेक्टर और अब भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह की देखरेख में हुआ था। बताया जा रहा है कि लोक के लोकार्पण की जल्दबाजी में भारी घटिया क्वालिटी का निर्माण करवाया गया है और ठेकेदारों के साथ-साथ खुद आशीष सिंह ने खूब पैसा खाया है। आपको बता दें कि भोपाल आने से छह माह पहले आशीष सिंह उस समय चर्चाओं में आ गए थे जब लोकायुक्त ने तीन आइएएस ऑफिसर सहित 15 लोगों को तलब किया था। आशीष सिंह इससे पहले इंदौर नगर निगम कमिश्नर, फिर उज्जैन कलेक्टर और अब भोपाल कलेक्टर। 2010 बैच के आइएएस ऑफिसर आशीष सिंह की सबसे पहली पदस्थापना कटनी जिले में अपर कलेक्टर के पद पर हुई थी। इसके बाद वे इंदौर जिला पंचायत के सीईओ बने। उज्धैन नगर निगम कमिश्नर के बाद देवास कलेक्टर बने। इसके बाद इंदौर नगर निगम के कमिश्रनर बनाए गए। इसके बाद वे उज्जैन कलेक्टर बने। महाकाल लोक का निर्माण आशीष सिंह के ही कार्यकाल में पूरा हुआ है। आशीष सिंह सीएसजेएम विश्वविद्यालय कानपुर से बीए करने के बाद आईएएस में आए थे। उज्जैन कलेक्टर के तौर पर आशीष सिंह ने 33 महीने तक जिले की कमान संभाली। इन्हीं की कार्यकाल में कोविड के शुरुआती दौर में देश की सर्वाधिक मृत्यु दर उज्जैन में रही। 2016 के सिंहस्थ के समय भी आशीष सिंह उज्जैन नगर निगम के आयुक्त थे। उस समय भी निर्माण कार्यों और घटिया निर्माण कार्यों के कई मामले सामने आये थे। कई कार्यों में फिजूलखर्ची की गई थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आशीष सिंह जहां-जहां रहे। वहां भ्रष्टाचार को लेकर चर्चाएं गरम रहती थी।

चालान नहीं हुआ। इसी कारण यहाँ खुलकर लूट-खसोट हो रही है। महाकाल मंदिर के वीआईपी कल्चर के कारण उज्जैन के श्रद्धालुओं को बड़ी अड़चन है। देश का पहला मंदिर है जहाँ भारी अवैध वसूली हो रही है। श्रद्धालु आते है उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। चोरी चकारी, जनधन का अपव्यय की रोक तभी संभव है जब यहाँ अन्य मंदिरों की तरह सामान्य नागरिकों की तरह दर्शन हो। महाकाल लोक के निर्माण के बाद उमड़ी भीड़ की आड़ में यहाँ हुई एक सौ करोड़ की

← Tweet

Shivraj Singh Chouhan
@ChouhanShivraj

उज्जैन में श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर के विस्तार का कार्य पूर्ण होने पर भव्य, दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप सामने आएगा। मंदिर परिसर के विस्तार में श्रद्धालुओं को सुविधा भी पहले से ज्यादा मिलेगी। श्री महाकाल जी से प्रार्थना है कि हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।

Translate Tweet

महाकाल लोक निर्माण के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सपत्निक निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। उस समय मुख्यमंत्री ने महाकाल लोक में हो रहे निर्माण कार्यों की काफी सराहना की थी।

लूट को भुला दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहाँ भी जाते हैं वहां एक लोक की घोषणा कर देते हैं। ओंकारेश्वर गये तो वहाँ पर एकात्म लोक की घोषणा कर दी, ओरछा गये तो रामलोक की घोषणा कर दी। इंदौर में अहिल्या लोक बनाने की

घोषणा कर दी। मतलब साफ है कि लोक का निर्माण करो और भ्रष्टाचार करो। शिवराज सरकार उधार लेकर साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्जा शासन पर हो जाने के बाद विकास कार्यो की जगह लोक बनाने का झूठा आश्वासन देकर जनता को भ्रमित

डोम कैमरा खरीदी घोटाला
दोगुनी कीमत से भी ज्यादा में खरीदे गये डोम कैमरे

महाकाल लोक के रिवाईज बिल ऑफ क्वांटिटी में आईसीटी कम्पोनेंट नॉन एसओआर के अंतर्गत लिये गये। यहां पर अनाप-शनाप भ्रष्टाचार किया गया। जैसे कि 04 मेगा पिक्सल हाई रिजोलेशन ड्रोन केमरा 2.8-8 एमएम फिक्सड लेंस आईआर इनेबल्ड के लिए 12000/- रूपये दर के हिसाब से 50 कैमरे खरीदे गये। कुल खरीदी 6 लाख रूपये की हुई है। खरीदे जाने वाले प्रोडेक्ट कंपनी स्पेसिफिक नहीं थे। जगत विजन द्वारा मामूली इंटरनेट पर पड़ताल करने पर पता चला कि एक अच्छी कंपनी का इंटरनेट पर उसी स्पेसिफिकेशन का ड्रोन कैमरा 4471/- मूल्य का आ रहा है। जबकि अगर बल्क में आर्डर दिया जाये तो यह मूल्य और भी कम होगा। इंस्टालेशन के बाद ज्यादा से ज्यादा एक कैमरा 6000 रूपये का मिल सकता था। इसका मतलब प्रति कैमरे पर लगभग दोगुने पैसों का भ्रष्टाचार हुआ है।

13. ICT Component

Sr. No.	Discription of Items	Unit	Rate	Qty	Amount
	ALL NONSOR ITEM				
1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of 4MP High Resolution Dome Camera, 2.8-8mm fixed lens, IR enabled, Varifocal auto iris lens as specified in the Tender Specifications	Each	12000	50	₹ 6,00,000.00
a	Supply	60%			
b	Installation	20%			
c	Testing & Commissioning	10%			
d	Handing Over	10%			

कर रही है। विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं।

महाकाल मंदिर का काला सच भी सामने आ गया है। गिनती के दौरान चढ़ोत्री चोरी करने वाले ऑनलाइन भस्म आरती, ऑनलाइन लड्डू प्रसाद, पैसे लेकर चोर रास्ते से इंट्री, पण्डे, पुजारी यहाँ पदस्थ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी जो अवैध वसूली कर रहे हैं। कई पकड़े गये उनके विरुद्ध थाना महाकाल में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये गये, किंतु हरेक में खारजी डाल दिया गया क्यों? पूर्व प्रशासक सोजन सिंह रावत यहाँ तीन बार पदस्थ रहे। फर्जी टेण्डरबाजी और तमाम चोर कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया था, उनको पुनः नौकरी पर रखकर उनके मार्फत रावत ने खूब हेराफेरी की। तमाम जांचें दबा दी गई। जो पण्डे, पुजारी अवैध वसूली में पकड़े गये उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने धर्मादे की रकम का जी भरकर दुरुपयोग किया। महाकाल में करोड़ों के निर्माण कामों में खूब हेराफेरी हुई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी दिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा

शिवराज सरकार ने किया प्रदेश की 8 करोड़ जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़

अधिक कीमत हुआ सामानों का भुगतान आंकड़े देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ

मूर्तियों के निर्माण व अन्य मद में जिस अधिकारी ने भुगतान किया उसने आपराधिक कृत्य किया है, उनके विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी होना चाहिए। 33 केवी का आइसोलेटर को बाजार कीमत से कई

सब स्टेशन खरीदी घोटाला

मूल कीमत की लगभग 30 प्रतिशत ज्यादा में खरीदे 03 सबस्टेशन

महाकाल लोक के महाभ्रष्टाचार के इस खेला में इन लोगों ने एक और भ्रष्टाचार किया जिसमें 11 के.वी., 315 केवीए का काम्पेक्ट सब स्टेशन जिसमें स्वीच गेयर, ट्रांसफार्मर, एलटी पैनल, आऊटर एक्सक्लोजर और स्काडा सिस्टम से लैस 21 लाख 60 हजार की कीमत से कम से कम 3 से 4 सब स्टेशन खरीदे गये। सब स्टेशन आम तौर पर गुगल में सर्च करने पर 18.50 का मार्केट में उपलब्ध है। निविदा में कोई भी वस्तु बांण्ड स्पेसिफिक नही थी अर्थात स्पेसिफिकेशन के आधार पर कान्ट्रेक्टर समान सप्लाई करना था। ऐसे में हमने जो मूल्य ऑनलाईन निकाली उससे और कम दर पर उक्त सामान की खरीदी हो सकती थी। यही सब-स्टेशन 15 लाख रुपये तक मिल जाना चाहिए था। जिसके लिये सरकार ने 21.60 लाख रुपये खर्च किये। गौर किया गया महाकाल लोक में बहुत सारी कार्य टेण्डर स्पेसिफिक नही थे। इसका फायदा उठाते हुए अधिकारियों की इच्छा अनुरूप ठेकेदार की मिलीभगत से खुल कर भ्रष्टाचार हुआ।

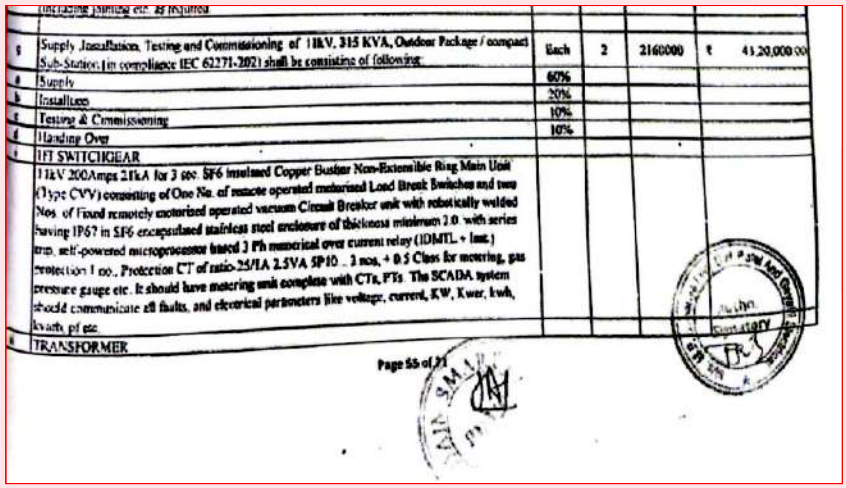

	including jointing etc. as required					
5	Supply Installation, Testing and Commissioning of 11kV, 315 KVA, Outdoor Package / compact Sub-Station (in compliance IEC 62271-2021) shall be consisting of following:	Each	2	2160000	₹	43,20,000.00
a	Supply	60%				
b	Installation	20%				
c	Testing & Commissioning	10%				
d	Handing Over	10%				
i	HT SWITCHGEAR					
	11kV 200Amps 21kA for 3 sec. SF6 insulated Copper Busbar Non-Extensible Ring Main Unit (Type CVV) consisting of One No. of remote operated motorised Load Break Switches and two Nos. of Fixed remotely motorised operated vacuum Circuit Breaker unit with robotically welded having IP67 in SF6 encapsulated stainless steel enclosure of thickness minimum 2.0 with series trip, self-powered microprocessor based 3 Ph numerical over current relay (IDMTL + Inst.) protection 1 no., Protection CT of ratio-25/1A 2.5VA 5P10 .. 3 nos, + 0.5 Class for metering, gas pressure gauge etc. It should have metering unit complete with CTs, PTs. The SCADA system should communicate all faults, and electrical parameters like voltage, current, KW, Kvar, kwh, kvarh, pf etc.					
ii	TRANSFORMER					

Page 55 of 71

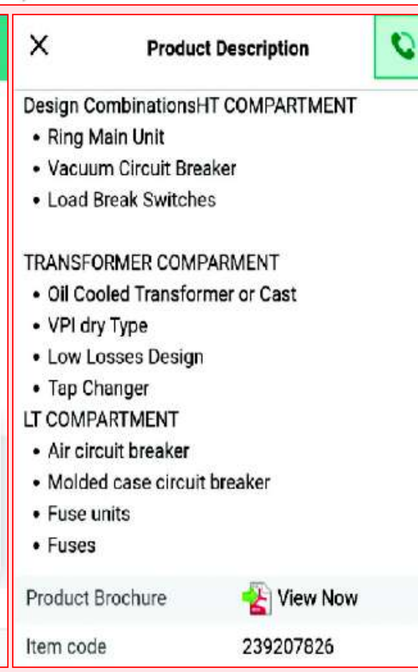

गुना महंगा 75 लाख रुपयों में खरीदा गया 2.8 डोम कैमरा 8 एमएम फिक्स लेंस की बाजार में कीमत 4471 रुपया हैं जो 6 लाख रुपयों में खरीदा गया, 4 एम.पी. सिक्यूरिटी बुलेट कैमरे का बाजार भाव 5750 रुपये है जो 12000 रुपये में खरीदे गये, 64 चैनल वाला विडियो रेकार्डर और कम्प्यूटर बाजार में 2.25 लाख रुपये में मिल जाते है जो कि 3.36 लाख रुपये में

पीटीजेड डोम केमरा घोटला

42,000 रूपये में बाजार में मिलने वाले कैमरे के लिए 1,06,400 रूपये का भुगतान किया गया

आईसीटी कम्पोनेंट में नॉन एसओआर आयटम पीटीजेड डोम कैमरा 1/1.9 सीएमओएस, इमेज संसर 3 मेगा पिक्सल कुल 15 कैमरे की खरीद 106400 रूपये प्रति कैमरे की दर से कुल 15.96 लाख की खरीदी की गई। जबकि यह कैमरा बाजार में 50 हजार रूपये तक में उपलब्ध है। मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार इस मामले में 200 प्रतिशत से ज्यादा कमीशन की सरकार बन गई है।

		10%				
3	Supply, Installation, testing and commissioning of PTZ Camera 1/1.9" CMOS Image sensor. 3 Mpx, MicroSD, Upto 300 degree Max 30fps@5Mp and 60fps@1080P resolution, H265 Powerful 35x Optical zoom - outdoor housing	Each	106400	15	₹	15,96,000.00
a	Supply	60%				
b	Installtion	20%				
c	Testing & Commissioning	10%				
d	Handing Over	10%				

खरीदा गया। मूर्तियों के भुगतान भी मनमाने किये गये।

महाकाल लोक निर्माण में करोड़ों के धन को डकारा है। इनमें मुख्यमंत्री को भी संज्ञान में था क्योंकि इनके खास मंत्री भूपेन्द्र सिंह महाकाल लोक निर्माण में शामिल रहे यही कारण था कि आधे अधूरे कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी से करवा लिया ताकि उनके द्वारा की हेराफेरी पर पलीता लगाया जा सके। इसमें जनरल फाइनेंशियल रुल 2017 और सेंट्रल विजलेंस कमीशन की गाइडलाइन की अवहेलना की गई। इनके नियमों को नजरअंदाज करके महाकाल लोक की प्रथम निविदा के पृष्ठ क्रमांक-4 पर मृदा

सरकार ने प्लास्टिक की मूर्तियां बनवा कर किया ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का अपमान

एफआरपी मतलब प्लास्टिक रिइन्फोर्स्ड की 100 मूर्तियां महाकाल लोक में लगाई ही नहीं जानी थी, क्योंकि यह तीर्थ ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में आता है। सरकार ने तर्क दिया कि एफआरपी भारत में कुछ मनोरंजन स्थल एवं कुछ मंदिरों में इस्तेमाल हुआ है पर वह भूल गये यहां पर यह महाकाल ज्योतिर्लिंग तीर्थ क्षेत्र है। समय का हवाला दिया जा रहा है कि पत्थर की मूर्तियां बनने में ज्यादा समय लेती है पर अयोध्या में 4-5 वर्ष में ही सारी मूर्तियां बना ली जायेगी। सरकार ने पहले एफआरपी से बनी मूर्तियों की उम्र 100 वर्ष बतलाई, फिर 10 वर्ष बतलाई। पर वास्तव में प्लास्टिक रिइन्फोर्स्डमेंट मौसमों के साथ डिफार्म होता जाता है भले ही आप इनको मजबूत कर दें पर समय के साथ इनमें विकृति आ ही जाती है और यह खंडित हो जाती है।

फेस-1 हेतु मात्र 97.71 करोड़ रुपयों की निविदा जारी की गई, जिसकी समयावधि 18 माह थी 36 माह डिफेक्ट लायबिलिटी कार्यकाल रखा गया। 97.71 करोड़ को

स्टोन वर्क घोटाला
मूर्ति इन्स्टॉल होने के बाद क्यों दिया गया हेंडलिंग चार्ज?

देश में पहली बार घोटाला करने के लिए नए तरीके इस्तेमाल हुए। जैसा कि ज्ञात है स्टोन कंपोनेंट में 50-50 का रेश्यो होता है अर्थात जितने का पत्थर की कीमत करीब करीब उतनी ही पत्थर पर आर्ट, लेबर, इंस्टालेशन और कमीशनिंग करने की कीमत होती है। उज्जैन में महाकाल लोक निर्माण में शिवराज सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के सारे पैमाने तोड़ दिए गए। कुल 84.24 लाख के शिव स्तंभ पर मूर्ति के लिए 16.84 लाख रुपए खर्च किए। मूल सिद्धांत से कुल खर्चा 32-35 लाख (जिसमें लेबर, इंस्टालेशन, पेंट, पॉलिश इत्यादि सब शामिल) तक होना था, पर इसे 84.24 लाख खर्चा किया गया। 20 प्रतिशत स्टोन की मूल्य थी बाकी 80 प्रतिशत डिजाइन, फिनिशिंग, कार्विंग, इंस्टालेशन एंड फिक्सिंग और हैंडलिंग ओवर में खर्चे किए गए। महाकाल लोक की प्रथम निविदा में कुल स्टोन कार्य के लिए 40.00 करोड़ रखे गए जिसे बाद में 73.55 करोड़ कर दिए।

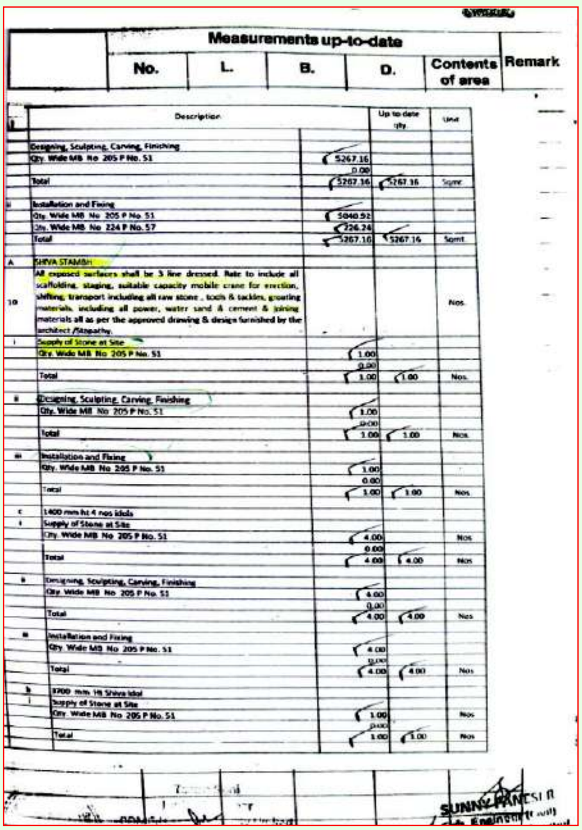

	Measurements up-to-date					Remark
	No.	L.	B.	D.	Contents of area	

	Description		Up to date qty	Unit
	Designing, Sculpting, Carving, Finishing			
	Qty. Wide MB No 205 P No. 51	5267.16		
		0.00		
	Total	5267.16	5267.16	Sqmt
ii	Installation and Fixing			
	Qty. Wide MB No 205 P No. 51	5040.92		
	Qty. Wide MB No 224 P No. 57	226.24		
	Total	5267.16	5267.16	Sqmt
A	SHIVA STAMBH			
10	All exposed surfaces shall be 3 line dressed. Rate to include all scaffolding, staging, suitable capacity mobile crane for erection, shifting, transport including all raw stone, tools & tackles, grouting materials, including all power, water sand & cement & joining materials all as per the approved drawing & design furnished by the architect /Stapathy.			Nos.
i	Supply of Stone at Site			
	Qty. Wide MB No 205 P No. 51	1.00		
		0.00		
	Total	1.00	1.00	Nos.
ii	Designing, Sculpting, Carving, Finishing			
	Qty. Wide MB No 205 P No. 51	1.00		
		0.00		
	Total	1.00	1.00	Nos.
iii	Installation and Fixing			
	Qty. Wide MB No 205 P No. 51	1.00		
		0.00		
	Total	1.00	1.00	Nos
c	1400 mm ht 4 nos idols			
i	Supply of Stone at Site			
	Qty. Wide MB No 205 P No. 51	4.00		Nos
		0.00		
	Total	4.00	4.00	Nos
ii	Designing, Sculpting, Carving, Finishing			
	Qty. Wide MB No 205 P No. 51	4.00		
		0.00		
	Total	4.00	4.00	Nos
iii	Installation and Fixing			
	Qty. Wide MB No 205 P No. 51	4.00		
		0.00		
	Total	4.00	4.00	Nos
b	3700 mm Ht Shiva Idol			
i	Supply of Stone at Site			
	Qty. Wide MB No 205 P No. 51	1.00		Nos
		0.00		
	Total	1.00	1.00	Nos

SUNNY PANESAR

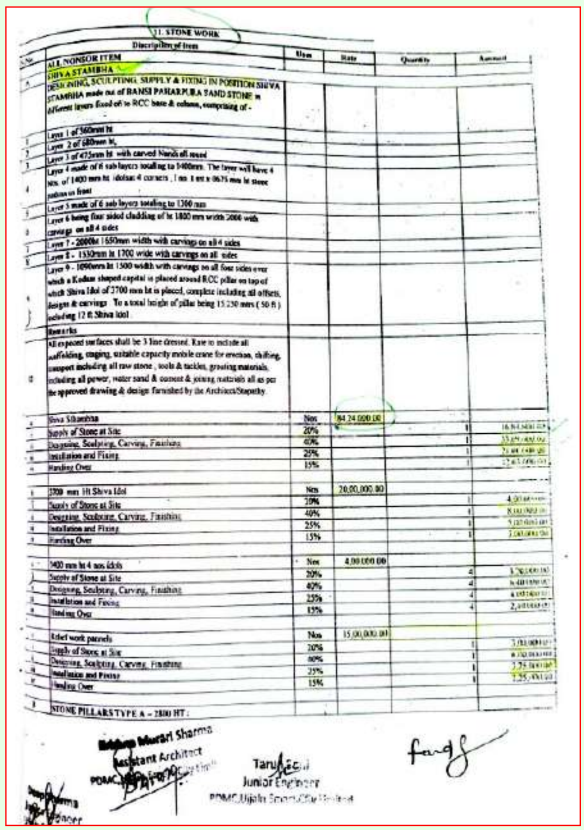

11. STONE WORK

S.No	Description of Item	Unit	Rate	Quantity	Amount
	ALL NONSOR ITEM				
	SHIVA STAMBHA				
A	DESIGNING, SCULPTING, SUPPLY & FIXING IN POSITION SHIVA STAMBHA made out of BANSI PAHARPURA SAND STONE in different layers fixed on to RCC base & column, comprising of -				
1	Layer 1 of 560mm ht				
2	Layer 2 of 680mm ht,				
3	Layer 3 of 475mm ht with carved Nandi all round				
4	Layer 4 made of 6 sub layers totalling to 1400mm. The layer will have 4 Nos. of 1400 mm ht idols at 4 corners, 1 no 1 set x 0675 mm ht stone ... in front				
5	Layer 5 made of 6 sub layers totalling to 1300 mm				
6	Layer 6 being four sided cladding of ht 1800 mm width 2000 with carvings on all 4 sides				
7	Layer 7 - 2000ht 1650mm width with carvings on all 4 sides				
8	Layer 8 - 1550mm ht 1700 wide with carvings on all sides				
9	Layer 9 - 1090mm ht 1500 width with carvings on all four sides over which a Kodum shaped capital is placed around RCC pillar on top of which Shiva Idol of 3700 mm ht is placed, complete including all offsets, designs & carvings. To a total height of pillar being 15.230 mrs (50 ft) including 12 ft Shiva Idol				
	Remarks				
	All exposed surfaces shall be 3 line dressed. Rate to include all scaffolding, staging, suitable capacity mobile crane for erection, shifting, transport including all raw stone, tools & tackles, grouting materials, including all power, water sand & cement & joining materials all as per the approved drawing & design furnished by the Architect/Stapathy.				
a	Shiva Sthambha	Nos	84,24,000.00		
i	Supply of Stone at Site	20%		1	16,84,800.00
ii	Designing, Sculpting, Carving, Finishing	40%		1	[illegible]
iii	Installation and Fixing	25%		1	[illegible]
iv	Handing Over	15%		1	[illegible]
b	3700 mm Ht Shiva Idol	Nos	20,00,000.00		
i	Supply of Stone at Site	20%		1	4,00,000.00
ii	Designing, Sculpting, Carving, Finishing	40%		1	8,00,000.00
iii	Installation and Fixing	25%		1	[illegible]
iv	Handing Over	15%		1	[illegible]
c	1400 mm ht 4 nos idols	Nos	4,00,000.00		
i	Supply of Stone at Site	20%		4	[illegible]
ii	Designing, Sculpting, Carving, Finishing	40%		4	[illegible]
iii	Installation and Fixing	25%		4	[illegible]
iv	Handing Over	15%		4	[illegible]
d	Relief work panels	Nos	15,00,000.00		
i	Supply of Stone at Site	20%		1	[illegible]
ii	Designing, Sculpting, Carving, Finishing	40%		1	[illegible]
iii	Installation and Fixing	25%		1	[illegible]
iv	Handing Over	15%		1	[illegible]
B	STONE PILLARS TYPE A – 2800 HT :				

Murari Sharma
Assistant Architect
PDMC

Tarun
Junior Engineer
PDMC Ujjain Smart City Limited

स्मार्ट सिटी बोर्ड की 21वीं बैठक में 97.71 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 177 करोड़ कर दिया और आगामी बैठक में यह रकम बढ़ाकर 196 करोड़ रुपया कर दिया। नियमानुसार 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि भावों और आयटम रेट के आधार पर बढ़ाये

विडियो रिकार्डर घोटाला

2.25 लाख का विडियो रिकार्डर और कम्प्यूटर के लिए 3.36 लाख का भुगतान किया

पूर्व के भांति आईसीटी कम्पोनेंट में शासन द्वारा 64 चैनल नेटवर्क विडियो रिकार्डर के साथ इन्टेल जैनॉन हैक्स कोर प्रोसेसर 2.2 हर्टज, 8 एमबी कैच, 16 टीबी हार्डडिस्क के साथ 45 कमरों की कैपेसिटी हेतु 3.36 लाख प्रति आयटम से खरीदा गया। जबकि बाजार में वहीं विशेषता का सामान 2.25 लाख में उपलब्ध है। दरअसल यह नॉन एसओआर आयटम में जिसकी जो मर्जी चली उतने का स्टीमेट बनवा कर भुगतान किया गया।

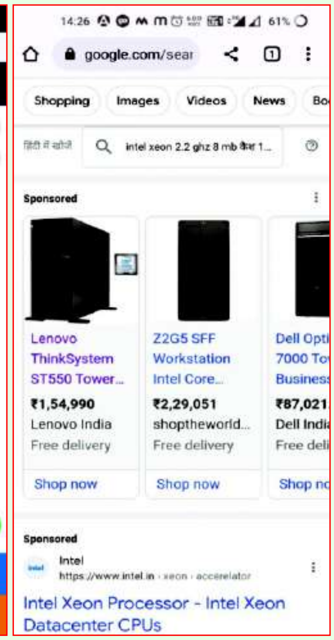

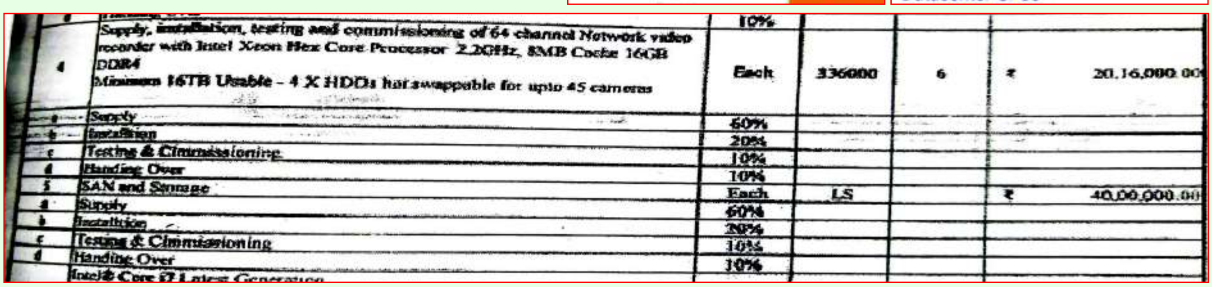

		10%				
4	Supply, installation, testing and commissioning of 64 channel Network video recorder with Intel Xeon Hex Core Processor 2.2GHz, 8MB Cache 16GB DDR4 Minimum 16TB Usable - 4 X HDDs hot swappable for upto 45 cameras	Each	336000	6	₹	20,16,000.00
a	Supply	60%				
b	Installation	20%				
c	Testing & Commissioning	10%				
d	Handing Over	10%				
5	SAN and Storage	Each	LS		₹	40,00,000.00
a	Supply	60%				
b	Installation	20%				
c	Testing & Commissioning	10%				
d	Handing Over	10%				
	Intel® Core i7 Latest Generation					

अंशुल गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, स्मार्ट सिटी द्वारा जब भ्रष्टाचार की परतें खोली गई तो उन्हें रास्ते से तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने हटवा दिया। ऐनकेन प्रकारेण से उनकी शिकायत कराई जाती थी। उनकी सच्चाई तब सामने आयी जब लोकायुक्त को केवल उनकी शिकायत की गई पर जांच करने पर भ्रष्टाचार में अन्य लोगों को शामिल होना पाया गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हवाला देकर कार्यक्रम से दो दिन पहले उज्जैन से स्थानांतरण करवा दिया गया।

जा सकते हैं 100 प्रतिशत नहीं। निविदा के पृष्ठ क्रमांक- 11 पर निविदा की सुरक्षा निधि 48.86 लाख रखी गई जो सीवीसी गाइडलाइन और जीएफआर के नियमों के अनुसार कम रखकर ठेकेदार को अनाधिकृत लाभ पहुँचाया। अपनी चहेती फर्म को काम देने के लिये निविदा के पृष्ठ क्रमांक- 14 पर ज्वाइंट वेंचर में तीन कंपनियों को मिलाकर इस निविदा के लिये लागू किया गया। ज्वाइंट वेंचर करवाकर पेटी कांट्रेक्टर से सारे कार्य करवाये गये। महाकाल लोक का टेण्डर स्पेसिफिक नहीं कराया गया। आयटम रेट तय नहीं किये गये ठेकेदार को मनमाना भुगतान अधिकारियों ने करवाकर भारी कमीशन वसूला गया। भुगतान ठेकेदार की इच्छानुसार कराये गये। महाकाल लोक के लिये आयसीटी से खरीदे गये सामान के फीचर्स और कांफ्रीगेशन टेण्डर से अलग है।

निविदा के पृष्ठ क्रमांक- 139 पर

बिना पर्यावरण अनुमति के बना महाकाल लोक

महाकाल लोक के निर्माण हेतु पर्यावरण अनुमति (EC) नही ली गई जबकि ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट में या तो केन्द्र सरकार केटेगिरी ए या राज्य सरकार केटेगिरी बी या बी-1 हेतु कोई भी रिपोर्ट पर्यावरण विभाग में जमा नही की गई। इस प्रोजेक्ट हेतु फार्म-ए नही बनाया गया जबकि ऐसे ही सौन्दर्यीकरण प्रोजेक्ट जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर जोकि बनारस में बनाया गया उसमें पर्यावरण अनुमति ली गई। गौर करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार ने महाकाल लोक के लिये इतनी जल्दबाजी की कि नियत कानूनों की धज्जिया उड़ाई गई। महाकाल लोक प्रोजेक्ट भगवान श्रीमहाकाल मंदिर के पवित्र रुद्रसागर के ग्रीन बेल्ट में बनाया गया जिसके लिये (EC) लेना अनिवार्य था।

Proposed Development of Shri Kashi Vishwanath Dham, Manikarnika Ghat and its Beautification at Varanasi, Uttar Pradesh.

Form 1 Page: 1 of 12

APPENDIX II
(See paragraph 6)

FORM-1A
(Only for construction projects listed under item 8 of the Schedule)

CHECK LIST OF ENVIRONMENTAL IMPACTS

(Project proponents are required to provide full information and wherever necessary attach explanatory notes with the Form and submit along with proposed environmental management plan & monitoring programme)

1. LAND ENVIRONMENT

1.1 Will the existing land-use get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings? (Proposed land use must conform to the approved Master Plan / Development Plan of the area. Change of land-use if any and the statutory approval from the competent authority are submitted). Attach Maps of (i) site location, (ii) surrounding features of the proposed site (within 500 meters) and (iii) the site (indicating levels & contours) to appropriate scales. If not available attach only conceptual plans.

Location of the Project Site:

The proposed project is a Development of Shri Kashi Vishwanath Dham, Manikarnika Ghat and its Beautification located at Varanasi, Uttar Pradesh. It is connected with well laid road network. The proposed project site is earmarked for Development of Shri Kashi Vishwanath Dham, Manikarnika Ghat and its Beautification as per the local development plans and the proposed project is planned and designed as per the regulations and procedures laid down by the Local Authority. The location of the project site is shown in Annex. 1

Surrounding Features:

The project site is earmarked for Development of Shri Kashi Vishwanath Dham, Manikarnika Ghat and its Beautification as per the local development plan. The terrain of the project site is leveled. The site is devoid of any outcrops and is not covered by any notified forests or protected areas.

1.2 List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirements, connectivity, community facilities, parking needs etc.

Salient Features of the Project

Items	Details
Location	Varanasi, Uttar Pradesh
Plot area	42000 Sq.m.
Built up area	27969 sq.m.
Maximum height	14.68 m
Number of floors & basements	1. Godowlia Gate - G+1 2. Utility Block - G+1 3. Yatri Suvidha Kendra 1- G+1 4. Yatri Suvidha Kendra 2- G+2 5. Yatri Suvidha Kendra 3- G+1 6. Security office - G+3 7. Mandir Parisar - G 8. Mandir Chowk - G+3 9. Guest House (Tourist) - G+2 10. Nilkanth Pavilion - G+2

महाकाल लोक में लगने वाले पत्थर की मानक जानकारी देने की बजाय लिखा है अक्षर धाम मंदिर दिल्ली में लगे पत्थर की क्वालिटी देखे और उसी तरह के पत्थर पर यहाँ कार्य करना है। टेण्डर में न तो पत्थर की क्वालिटी बताई और नहीं उसकी ग्रेड और मोटाई आर्टवर्क स्टोन कार्य के लिये पत्थर की क्वालिटी न बताकर उचित शब्द का उपयोग किया गया। निविदा में कितने स्कोप की मूर्तियाँ होगी उसका उल्लेख तक नहीं किया गया। कितने साइज की कितनी मूर्तियाँ लगेगी और उनकी कीमत क्या होगी? इसका कोई उल्लेख नहीं है। सब

अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा महाकाल लोक

ठेकेदार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। मूर्तियों का भुगतान किस मापदण्ड से होगा इसके लिये ठेकेदार व भुगतान अधिकारी को खुला छोड़ दिया गया। इसलिये खुलकर मनमानी, कमीशनखोरी और नियम विरुद्ध भुगतान कराये गये। निविदा के मुताबिक निर्माण स्थल पर एक लेबोरेटरी स्थापित की जाकर ऑनसाइट टेस्ट किये जाने की शर्त थी, किंतु लेबोरेटरी ही स्थापित नहीं की गई। परिभाषित किये आयटम का तुलनात्मक विवरण बनाकर निविदा जारी कर दी गई। आयटम की रेट ठेकेदार की इच्छा पर छोड़ दिये तक गये सस्ता व

महाकाल लोक निविदा घोटाला
निविदा 97.71 करोड़ से सरकार ने 196 करोड़ किया

महाकाल लोक की प्रथम 97.71 करोड़ की निविदा जारी हुई, इस निविदा की समय अवधि 18 माह थी और डिफेक्ट लायबिलिटी 36 माह की थी। यह निविदा राशि 19वीं बैठक में 165.07 करोड़ की गई। उसके बाद 21वीं बैठक में 177.68 करोड़ की गई। जिसे अंतिम बार 196 करोड़ किया गया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार शुरुआती बजट को कुछ माह में दोगुना करने का पहला अवसर है। जबकि निविदा के अंतर्गत 10-20 प्रतिशत का ही प्रावधान रहता है। यही से महाकाल लोक के भ्रष्टाचार की नींव रखी गई।

UJJAIN SMART CITY LTD

COST SUMMARY FOR MRIDA PHASE-I

S.No.	Description	Tender Amount (INR) in Cr.	Amount approved in 19th BM in cr.	Amount approved in 21st BM in cr.	Amount as per actual in cr.	Difference in Cr.	Remarks
1	Public Plaza	₹ 9.60					
2	Mid Way Zone	₹ 3.51					
3	Mahakal Theme Park + Lake Front development	₹ 6.23					
5	Landscape and Horticulture	₹ 0.58	₹ 74.28	₹ 63.30	₹ 66.05	₹ 2.75	
6	Road work	₹ 5.00					
7	Dismentaling Work	₹ 0.11					
8	Boundry Wall	₹ 4.41					
9	Fire Fighting	₹ 1.41	₹ 3.46	₹ 1.60	₹ 1.06	₹ -0.54	
10	Plumbing Works	₹ 0.36	₹ 2.31	₹ 1.30	₹ 1.30	₹ -	
11	Stone Work	₹ 40.54	₹ 48.99	₹ 73.80	₹ 73.55	₹ -0.25	
12	Electrical Work	₹ 24.02	₹ 28.02	₹ 24.75	₹ 25.50	₹ 0.75	
13	ICT Component	₹ 1.95	₹ 1.95	₹ 1.95	₹ 2.05	₹ 0.10	
14	Smart Stambh Bracket		₹ -	₹ 0.48	₹ 0.48	₹ -	
	Total	₹ 97.71	₹ 159.01	₹ 167.18	₹ 169.99	₹ 2.81	
	BELOW 0.76% TP	₹ 0.74	₹ 1.21	₹ 1.27	₹ 1.29	₹ 0.02	
	AMOUNT AFTER TP	₹ 96.97	₹ 157.80	₹ 165.91	₹ 168.70	₹ 2.79	
	EXTRA ITEM AMOUNT (CIVIL+STONE)		₹ 7.27	₹ 11.77	₹ 8.87	₹ -2.90	
	OVERALL TOTAL AMOUNT		₹ 165.07	₹ 177.68	₹ 177.57	₹ -0.11	

* All figure in Crore.

Final = 197 Crore.

Deep Sharma
Junior Engineer
PDMC Ujjain Smart City Limited

Krishna Murari Sharma
Assistant Architect
PDMC Ujjain Smart City Limited

Page 1 of 1

लोकायुक्त के शिकंजे में फंसे भ्रष्ट अफसर

घटिया माल लगाकर साइट ठेकेदार ने कमीशनखोरों के साथ खूब लूट-खसोट की। निविदा के पृष्ठ क्रमांक- 142 द्वारा पर स्कोप ऑनवर्क में 25 आयटमों का हवाला है। मूर्तियां पत्थर की होनी चाहिये, किंतु तमाम मूर्तियां प्लास्टिक फायबर की बना दी गई। निविदा के पृष्ठ क्रमांक 105 व 106 में ठेकेदार को 18 माह में कार्य पूर्ण करना था जो 07 मार्च 2020 तक पूर्ण हो गई। ठेकेदार की मिलीभगत से अधिकारियों ने कोई पेनल्टी क्यों नहीं लगाई। निविदा के अनुसार एक ही पत्थर

बुलेट कैमरा घोटाला

6 से 7 हजार के बुलेट कैमरे के लिए दिये 12000 रूपये, कुल भुगतान 2,16,0000 रूपये का किया गया

महाकाल लोक के रिवाईज बिल ऑफ क्वांटिटी में आईसीटी कम्पोनेंट नॉन एसओआर के अंतर्गत लिये गये एक और खरीदी जिसमें भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा पार की गई वह है 04 मेगापिक्सल बुलेट कैमरा। स्पेसिफिकेशन के अनुसार यह कैमरा फ्लिकर लैस डिजीटल, सीई सनवाईजर, वेदर प्रुफ, हाऊसिंग माउंट, मेटल जैकेट, 2.8-8 एमएम फिक्सड लेंस, माईक्रो एचडी स्टोरेज, वर्टीकल लैंस 3.5 से 8 एमएम लैंस, 50 मीटर तक की कवरेज एवं अन्य कुल 180 कैमरे 12000/-रूपये प्रति कैमरे के हिसाब से कुल 2,16,0000/- का बीओक्यू हुआ। जगत विजन द्वारा बिलकुल वही तकनीकी विशेषता वाले कैमरो को जब इंटरनेट पर देखा गया तो 5750/-रूपये प्रति कैमरे से उपलब्ध है। ऐसे में इनकी दर बल्क खरीदी पर और कम रहती। भगवान श्री महाकाल के नाम पर जिस प्रकार सरकार ने लगभग हर खरीदी पर भ्रष्टाचार किया। ऊपर दर्शायी यह खरीदी तो नमूने भर हैं इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए तो 500 पन्नों की किताब भी कम पड़ेगी।

		10%				
2	Supplying, installing, testing and commissioning of 4MP bullet camera Flickerless Digital, CE with Sunvisor Day Night Weather Proof Housing mount/Metal Jacket, 2.8-8mm fixed lens, MicroSD storage IR enabled, 100dB WDR, H265, IP68, POE - UL/CE/FCC/EN Camera, wide angle, Auto Iris, Verifocal Lens of 3.5 to 8mm lens to cover 50 mtrs Distance with all accessories and hardware for fixing, complete as required.	Each	12000	180	₹	21,60,000.00
a	Supply	60%				
b	Installation	20%				
c	Testing & Commissioning	10%				
d	Handing Over	10%				

पर दीवार पर आकृतियां उकेरी जाना चाहिये थी। कई छोटे-छोटे पत्थर जोड़कर एक ही आकृति बनाई गई। आकृतियों की गहराई कम है। इसमें ठेकेदार को बड़ा लाभ पहुँचाया गया। महाकाल लोक में पत्थर की दीवारों पर प्लास्टिक की छत लगाकर उन पर पत्थरों जैसा रंग करवाकर आंखों में धूल झोंकी गई। दीवारों पर लगे पत्थरों को रुपया बगैर ब्लाक बालू व सीमेंट से चिपकाकर दिये गये जो श्रद्धालुओं के ऊपर गिरकर दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का

लक्ष्मण ठाकुर द्वारा की गई लोकायुक्त में शिकायत

लक्ष्मण ठाकुर पिता प्रेम सिंह ठाकुर उज्जैन ने 11 अक्टूबर 2022 को लोकायुक्त में शिकायत की। इसमें उन्होंने कॉन्ट्रेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने सीमेंट कांक्रीट की मोटाई ज्यादा बताई थी। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड में जो निमार्ण और सौन्दर्यीकरण का कार्य किया है उसकी अधिकतम राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है। टेंडर आईडी नम्बर 2020 यूएडी 112241-1 का जिक्र उन्होंने किया है जिसमें बेगमबाग अंडर ग्राउंड कार्य में एस्टीमेट से अलग लाल पत्थर के लिए टेंडर नहीं किया गया जिससे कीमत 30 से 40 प्रतिशत बढ़ गई। सीमेंट कांक्रीट की मोटाई वास्तविक कार्य से ज्यादा बताकर ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया एवं सरिये की मोटाई कम की गई। रूद्र सागर गहरी करण में डीवाटरिंग का आयटम नहीं था जिससे विभाग को 85 करोड़ का नुकसान हुआ।

महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ है- महेश परमार, विधायक

विधायक महेश परमार से बातचीत करती हुई जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक

महेश परमार तराना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। महेश परमार ने ही सबसे पहले महाकाल लोक के घोटाले को लेकर विधानसभा में मुददा उठाया और लोकायुक्त में शिकायत की थी। इस मामले को इतना उठाया गया कि सरकार को कठघरे में खड़ा होना पड़ा। महेश परमार की शिकायत के कारण ही महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर लोकायुक्त ने तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह सहित 15 लोगों को जबाव देने के लिए बुलाया। विधायक महेश परमार ने कहा कि जो लोग जब धर्म की बात करते है, जय-जय श्रीराम बोलते है तो भगवान महाकाल के नाम पर करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार क्यों किया। मां क्षिप्रा के क्षेत्र में आकर सब अधिकारी मिलकर ठेकेदारी करते हैं। 100 करोड़ रुपये खर्च करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रचार-प्रसार किया। वो राशि कहां से आयी। हजारों बसें पूरे मध्यप्रदेश से आई, उन बसों में 2-2, 4-4 लोग आये। 300 करोड़ रुपये कमलनाथ जी ने दिये और 100 करोड़ मोदी के प्रचार में खर्च किये। दुर्भाग्य की बात है। आज़ादी के बाद मध्यप्रदेश में 03 आईएएस और 12 लोगों के साथ कुल 15 लोगों पर लोकायुक्त में जांच चल रही है। इसमें सरकार जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी बात लोकायुक्त में जिस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई उस अधिकारी को हटा कर भोपाल कलेक्टर बना दिया गया। उज्जैन के तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम, आयुक्त, सब अधिकारी भ्रष्टाचार के दायरे में है। 01 करोड़ की निविदा स्मार्ट सिटी के माध्यम से निकाली। निविदा की जो शर्ते थीं वह टेण्डर के माध्यम से बदल दी गई। सरकार जिम्मेदार है और सरकार के खास आशीष सिंह जिम्मेदार है। पूरे देश से महाकाल के दर्शन के लिये श्रृद्धालु आते है और दान चढ़ाते हैं उस राशि का सरकारी उपयोग किया गया। दान की राशि को सरकारी बताकर खर्च कर दिया। इन्हीं सब मामलों को लेकर जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक ने उनसे संक्षिप्त रूप से बात की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश-

■ आपने लोकायुक्त में महाकाल लोक संबंधित भ्रष्टाचार की कंप्लेंट की है। उसके बारे में बताईये।

▶▶ मैंने महाकाल लोक की शिकायत लोकायुक्त में की, जिसे प्रारंभिक जांच के बाद सच माना गया और 15 अधिकारियों को नोटिस इश्यू हुआ है जिसमें तीन आईएएस अफसर हैं। इसमें प्रथिमिकी दर्ज हो गई है। सरकार ने स्वीकार किया है कि उसने महाकाल लोक में भ्रष्टाचार किया।

■ महाकाल से जुड़े निर्माण कार्यो में भ्रष्टाचार हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं?

▶▶ दरअसल भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ राम और हिंदू देवी देवताओं के नाम पर राजनीति करती है, महाकाल की बात करते हैं, पर कैसे बाबा महाकाल के पैसों की चोरी की। उनके नाम से बनने वाला महाकाल लोक में करोड़ों का भ्रष्टाचार कर दिया। मंदिर के पैसों में भ्रष्टाचार किया, आज कांग्रेस पार्टी सच्ची हिंदू हैं। हम लोग ईश्वर के सामने सर झुकाते हैं और ऐसे पाप करना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। मध्यप्रदेश और उज्जैन की जनता की आस्था पर भ्रष्टाचार इस शिवराज सरकार ने की है।

■ लोकायुक्त की जांच के दायरे में आए अधिकारियों को क्या सरकार ने संरक्षण दिया है?

▶▶ सरकार ने लोकयुक्त में प्रथिमिकी दर्ज अधिकारी को प्रमोट करके पहले मलाईदार पोस्टिंग दी। फिर भोपाल कलेक्टर बना दिया। सच सबके सामने आ गया। शिवराज ने भगवान महाकाल को लूटने वाले आशीष सिंह को भोपाल कलेक्टर बना दिया।

उपयोग किया गया। मूर्तियों के हाथ पैर आड़े टेड़े होने लगे हैं। मूर्तियों की शकलें धूप में बदल रही हैं। उनके स्ट्रक्चर टूटने लगे हैं। ठेकेदार को इनके भुगतान एम.बी. व निविदा के तुलनात्मक अध्ययन के बाद किये जाना चाहिये, किंतु बगैर आधार के

आखिर किसके निर्देश पर हुआ महाकाल मंदिर की सुरक्षा एजेंसी घोटाला

विगत डेढ़ वर्षो से महाकाल मंदिर की आंतरिक सुरक्षा का ठेका बगैर टेण्डर कृष्णा कम्पनी से करवाया जाता था, किंतु निविदा क्रमांक 4823 दिनांक 22-12-2022 जारी करके 20 करोड़ का टेण्डर 300 सुरक्षा कर्मियों के लिये जारी किया, 31.1.2023 को जारी संशोधन में 300 सुरक्षाकर्मियों से बढ़ाकर 500 सुरक्षा कर्मचारी बताकर इसमें कई संशोधन करवा दिये गये। 2017 में कराये गये टेण्डरों से कई गुना ज्यादा। जबकि महाकाल की आंतरिक सुरक्षा का ठेका सीआईएसएफ को दिया जाना था और उनसे आंतरिक सुरक्षा का सर्वे भी करवा लिया था, जिसका भुगतान महाकाल प्रबंध समिति द्वारा 8.50 लाख रुपयों का कर दिया गया था, किंतु केन्द्र सरकार की एजेंसी से काम करवाने का कमीशन इन कमीशनखोरों को नहीं मिलता है। इसलिये टेण्डर जारी कर दिया गया। इतने महत्वपूर्ण टेण्डर में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उसका टेण्डर जारी करने के बाद उसका संशोधन जारी करवाया गया। इस फर्जीवाड़े में प्रशासक संदीप सोनी के कलेक्टर का साथ देने से मना करने पर सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल से हस्ताक्षर करवाये गए। यहां आशीष सिंह को हस्ताक्षर करवाने की इतनी जल्दी क्या थी, जबकि उनके स्थानांतरण के आदेश आ गये थे। इस संशोधन में जिस ठेकेदार के आड़े आने वाली शर्त टेण्डर के पृष्ठ 12 की शर्त क्रमांक 12 व 13 को विलोपित करना, सिक्यूरिटी 5 प्रतिशत को घटाकर 3 प्रतिशत करना, ऐसी शर्त नहीं थी जिस पर संशोधन जारी करना था। इसकी अंतिम दिनांक 06 फरवरी थी जिसे 22 फरवरी कर दिया गया था।

महाकाल मंदिर समिति का बैंक खाता और एफडी राष्ट्रीयकृत बैंक में करवाई जाने का प्रावधान महाकाल मंदिर एक्ट में ही है। किंतु निजी बैंकों में एफडी करवाने और उनको उपकृत करके स्वयं का फायदा करवाने का धंधा वर्षो से चल रहा है। पूर्व में ज्यादा ब्याज का हवाला देकर एक निजी बैंक ऐक्सिस बैंक में करोड़ों रुपया जमा करवाया गया था, फिर तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने लाखों रुपयों की एफडी आईसीआईसीआई बैंक में जमा करवा दी और इसी बैंक से बगैर टेण्डर करवाये एक करोड़ का फर्जी भुगतान इंदौर के ठेकेदार अरण्य जैन को करवा दिया गया।

बड़े भुगतान कर दिये गये। महाकाल लोक देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका पर्यावरण क्लियरेंस नहीं है। इन संरचनाओं में मिट्टी, मूरम की जगह मिट्टी भरवा दी गई। महाकाल लोक कारिडोर में विज्ञापन हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया और दैनिक भास्कर के ई में कोर्ट चलवा दिये। इन ई कोर्ट पर एसबीआई और दैनिक भास्कर अपने विज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं। जबकि

भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के जरिया बने ये कार्य

- **निविदा घोटाला -** प्रथम निविदा में बजट 97.71 करोड़ से कुछ ही समय में 196 करोड़ कर दिया गया। इसका मतलब 5 रूपये की चाय बनने से पहले ही सरकार ने उसे 10 रूपये की कर दी।
- **निविदा सुरक्षा निधि घोटाला -** ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए सुरक्षानिधि 48.85 लाख रखी जोकि सीवीसी की गाईडलाईन और जीएफआर के नियमानुसार बहुत कम है।
- **कॉन्ट्रेक्टर घोटाला -** अपनी पसंदीदा फर्म को लाभ देने के लिये ज्वाइंट वेंचर में तीन कंपनियों को निविदा दिलवायी गई, जबकि पूरा काम पेटी कान्ट्रेक्टर से कराया गया।
- **महाकाल लोक स्टोन वर्क घोटाला —** पहले बजट में इस कार्य के लिये 40 करोड़ से कुछ समय बाद 73.55 करोड़ कर दिया जिसमें स्टोन की मूल्य 20 प्रतिशत है, शेष 80 प्रतिशत डिजाईन, फिनिशिंग और हेंडलिंग ओवर के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया।
- **वीसीबी आयसोलेटर घोटाला -** सरकार ने महाकाल लोक में 75 लाख का आईसोलेटर खरीदा जोकि बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा था।
- **सबस्टेशन घोटाला -** महाकाल लोक में 11 केवी के 2160000/- के सबस्टेशन खरीदे गये वह बाजार से 30 प्रतिशत ज्यादा कीमत पर खरीदे गये।
- **ठेकेदार अधिकारी मिलीभगत -** महाकाल लोक में ज्यादातर कराये गये कार्य टेंडर स्पेसिफिक नहीं थे। किसी प्रकार के आयटम तय नहीं किये गये थे। ठेकेदार और अधिकारियों के विवेक पर छोड़कर खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया।
- **महाकाल लोक पत्थर ग्रेड घोटाला-** निविदा में पृष्ठ क्रमांक 139 में उल्लेखित है कि अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में लगे पत्थर की गुणवत्ता वाले का उपयोग किया जाना है, किन्तु यहां न पत्थर की गुणवत्ता बताई गई और न ही ग्रेड।
- **महाकाल लोक लेबोरेटिरी घोटाला —** निविदा के अनुसार निर्माणाधीन स्तर पर ऑनसाईट लेबोरेटिरी स्थापित की जानी थी पर कोई भी लेबोरेटिरी गुणवत्ता परीक्षण के लिए स्थापित नहीं की गई।
- **महाकाल लोक कम्प्यूटर घोटाला -** महाकाल लोक में 90 हजार के कम्प्यूटर के लिए 1.5 लाख का भुगतान किया गया। ऐसे 06 कम्प्यूटर खरीदे गये।
- **मूर्ति भुगतान घोटाला —** निविदा में स्कोप आफ वर्क में कितने आकार की मूर्तियां, उनकी कीमत और उनकी गुणवत्ता का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ठेकेदार और अधिकारी के मनमुताबिक भुगतान किया गया।
- **निविदा डिटेल घोटाला -** महाकाल लोक के निर्माण हेतु टेंडर से ही डिटेल विवरण न बनाते हुये आंकलात्मक विवरण निविदा में बनाया गया। इसके साथ ही निविदा में आयटम और दर ठेकेदार और अधिकारी की इच्छा पर छोड़ दिया गया ताकि सस्ता व घटिया माल लगाकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा सके।

महाकाल लोक की ई कोर्ट निविदा जारी की जाती तो मंदिर को करोड़ों की आय होती। इसका लाभ कई अधिकारियों ने बंदरबांट से बांट लिया। महाकाल लोक की मूर्तियों की डिजाइन धर्म के अनुसार हो इसके लिये संगीता बेस की नियुक्ति की गई। इसे 22 हजार रुपये प्रतिदिन के मान से भुगतान किया गया। जबकि गूगल से प्रिंट निकालकर मूर्तियाँ बनवा दी गई। संगीता

- **ड्रोन कैमरा घोटाला –** नॉन एसओआर आयटम होने के कारण इन जैसी वस्तुओं की खरीदी में मनमाफिक भ्रष्टाचार हुआ। जैसे बाजार में 5-6 हजार इंस्टालेशन सहित मिलने वाले कैमरे के लिए 12000/- रूपये का भुगतान किया गया।
- **प्लास्टिक मूर्ति घोटाला –** निविदा में स्टोन ऑन वर्क में 25 आयटमों का हवाला था। मूर्तियां जो पत्थर की बननी चाहिए थी उसे मोटे कमीशन के कारण निविदा के विपरीत फाईबर रीइनफोर्ज्ड प्लास्टिक (एफआरपी) से बनाई गई।
- **पीटीजेड ड्रोन कैमरा घोटाला –** निविदा में उल्लेखित कैमरे के स्पेसिफिकेशन अनुसार 42000/- रूपये में इंस्टालेशन सहित बाजार में मिलने वाले कैमरे के लिए 106400/- रूपये का भुगतान किया गया।
- **महाकाल लोक अन्य मूर्ति घोटाला -** महाकाल लोक के ऊपर की साईड की दीवारों पर पत्थर के स्थान पर प्लास्टिक शीट को रंग करवाये जाकर लगाया गया एवं दीवार पर लगे पत्थर को बिना लॉक करे बालू और सीमेंट लगाया गया है।
- **महाकाल लोक पर्यावरण अनुमति घोटाला -** महाकाल लोक के निर्माण के लिए कोई भी पर्यावरण अनुमति नहीं ली गई, जबकि काशी विश्वनाथ कॉरीडोर प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण अनुमति ली गई थी।
- **नेटवर्क वीडियो रिकार्डर घोटाला -** महाकाल लोक में 06 नेटवर्क वीडियो रिकार्डर और कम्प्यूटर के लिए 3,36,000/- रूपये प्रति नग के हिसाब से भुगतान किया गया। जबकि बाजार मूल्य 2,25,000/- रूपये में यह वीडियो रिकार्डर उपलब्ध है।
- **महाकाल लोक पेटी ठेकेदार घोटाला -** महाकाल लोक में अधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए खास पेटी ठेकेदारों को कार्य दिया जिसमें महाकाल लोक में रेत, गिट्टी के स्थान पर मिट्टी का भराव किया गया।
- महाकाल लोक में स्मार्ट सिटी उज्जैन में आर्किटेक्ट नितिन श्रीमाली को 65 हजार रूपये प्रतिदिन के भुगतान पर रखा। नितिन श्रीमाली को बिना निविदा के रखा गया।
- महाकाल लोक में मूर्तियों के डिजाईन हेतु संगीता बैस को 22 हजार रूपये प्रतिदिन के भुगतान पर रखा गया। इनको भी बिना निविदा के विज्ञापन के सीधे रखा गया जिससे अधिकारियों को सीधा लाभ मिल सके। जबकि देश में अयोध्या स्थित मंदिर के निर्माण हेतु बड़े-बड़े मूर्तिकार रखे गये हैं।
- **बुलेट कैमरा घोटाला -** महाकाल लोक में 04 मेगा पिक्सल के बुलेट कैमरा के लिए 12000/- रूपये प्रति कैमरे के हिसाब से 180 कैमरे खरीदे गये। जबकि बाजार में यह कैमरे 6-7 हजार में उपलब्ध हैं।
- **महाकाल लोक पौधा घोटाला -** जहाँ मुफ्त में पौधे उपलब्ध होते हैं वहाँ ठेकेदार ने पौधों के नाम खूब लूटा। लंताना कामरा आरेंज के पौधे 640 रुपये नग, लंताना कामरा आरेंज 135 रुपये नग, सत्यर्णी 85 रुपये प्रति नग, शीशम 97.50 रुपये प्रति नग, क्लासिक फिश्चुला 97.50 प्रति नग, परिजात का पौधा 97.50 रुपये प्रति नग, आम 260 रुपये प्रति पौधा, जामुन 187 रुपये प्रति पौधा, गुलर 195 रुपये प्रति पौधा, अफ्रीकन टूलीप 195 रुपये प्रति पौधे खरीदे गए। अब ये पौधे गायब हैं। बिलों के भुगतान हो गये। किसी भुगतान का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया।
- **महाकाल लोक घोटाला ही घोटाला -** महाकाल लोक की बिल आफ क्वांटिटी, निविदा और मेजरमेंट बुक की जांच करने के बाद निष्कर्ष आया कि लगभग हर बिल में भ्रष्टाचार किया गया। उपरोक्त भ्रष्टाचार तो सागर में बूंद भर जैसे है, वरना इनका उल्लेख करने में 500 पन्नों की किताब भी कम पड़ जायेगी।

बेस को बगैर विज्ञप्ति या विज्ञापन कैसे रख लिया गया? रिकार्ड से स्मार्ट सिटी के कई रिकार्ड गायब करवा दिये गये हैं। महाकाल लोक के कार्य आदेश क्रमांक 218 दिनांक 7-3-2019 के बिल नंबर 31 की एम.बी. के पृष्ठ क्रमांक 09 पर फायबर और प्लास्टिक के कार्य के लिए 9 फीट 2.97 लाख रूपये, 10 फीट के 4.67 लाख रूपये, 11 फीट के लिए 8.50 लाख रूपये

महाकाल लोक निर्माण में महालूट के आंकड़े

प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक के निर्माण में भारी लूट और भ्रष्टाचार किया गया है। इस निर्माण में उज्जैन स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों ने ठेकेदारों को भारी फर्जी भुगतान किया है। खर्च की 300 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होने का दावा करने वाले ये अफसर भ्रष्टाचार के दायरे में हैं। शिवराज सिंह सरकार को महाकाल लोक के निर्माण का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना चाहिए था लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। हरेक निर्माण या सप्लाय में 60 प्रतिशत कीमत, 20 प्रतिशत इंस्टालेशन, 10 प्रतिशत टेस्टिंग और कमीशननिंग व रुद्र सागर के डीवाटरिंग का भुगतान ठेकेदार को बगैर टेण्डर 85 लाख का भुगतान किया गया। निर्माण की गुणवत्ता जांचने के ठेकेदार के विरुद्ध कोई जुर्माना लिये टेण्डर की शर्त के अनुसार निर्माण स्थल पर लेबोरेटरी की स्थापना नहीं करके जुर्माना नहीं किया। तमाम भुगतान गुणवत्ताविहीन कार्य कराये गये। महाकाल सिंधी कॉलोनी में स्थित झूलेलाल की 31 फीट ऊंची मूर्ति ठेकेदार ने लगभग 4.50 लाख रुपयों में बनाकर दी। इसी मटेरियल की मूर्ति महाकाल लोक में 15 फीट की मूर्ति लगाई गई और जिस ठेकेदार ने झूलेलाल की मूर्ति बनाई थी उसी ठेकेदार ने बनाई। इसके

और 15 फीट के लिए 10.2 लाख रूपये का भुगतान किया गया। कार्यदेश क्रमांक 218 दिनांक 7.3.2019 की एमबी नंबर 31 के पृष्ठ क्रमांक 13 पर 4 फीट उंचाई के 3.4 लाख रूपये, 12 फीट के लिए 17 लाख रूपयों के भुगतान किये गए।

निर्माण के 10.02 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इस मामले की भी कोई जांच नहीं कराई गई।

महाकाल लोक में भारी लूट हुई है इसे समझते हैं। घटिया और स्तरहीन निर्माण कराया गया। टेण्डर की शर्त के अनुसार निर्माण स्थल पर गुणवत्ता की जांच के लिये निर्माण की हेराफेरी में पूरी तरह लिप्त है। भारत लेबोरेटरी की स्थापना की जाना थी, किंतु कमीशनखोर अफसरों ने इसे नजरअंदाज कर दिया गया। टेण्डर गोलमाल किया गया। 97.71 करोड़ का टेण्डर निकालकर ठेकेदार को फायदा पहुँचाने के लिये बाद में उसकी रकम 196 करोड़ कर दी। नियत समय में काम पूरा न होने पर बगैर मापदण्ड के कराये गये इसके निर्माण की गुणवत्ता की जनरल फायनेंशल रुल और सेंट्रल विजलेंस कमीशन के गाइडलाइन को धता बताकर खूब लूट-खसोट की। स्मार्ट सिटी के 45 करोड़ रुपये एक्सिस बैंक उज्जैन शाखा में जमा थे जो सरकार को ज्यादा ब्याज दे रही थी बैंक, किंतु भ्रष्ट अधिकारियों ने 45 लाख रूपये निकालकर कम ब्याज पर आईसीआईसीआई बैंक में जमा करवाकर बगैर टेण्डर या बगैर काम कराये इंदौर के एक ठेकेदार अरण्य जैन को एक करोड़ रूपये का भुगतान करवा दिया गया। ठेकेदार के भुगतान बिलों के अनुसार जिनका भुगतान किया गया उसमें सप्लाय का 60 प्रतिशत, स्टालेशन के 20 प्रतिशत, टेस्टिंग व कमीशनिंग का 10 प्रतिशत व हेण्डलिंग का 10 प्रतिशत वसूला यानि एक सौ रूपयों में 60 रूपये का सामान और 40 प्रतिशत जीन मदों में भुगतान किया गया। उसमें कमीशन किसे दिया गया यानि अधिकारियों की कमीशनखोरी का भुगतान भी स्मार्ट सिटी ने किया।

11 अक्टूबर 2022 को जब महाकाल लोक के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंदौर से बाय रोड उज्जैन आ रहे थे उस समय इंदौर से लेकर उज्जैन तक की सड़कों का सौन्दर्यीकरण के साथ आर्टिफिशियल पेड़ पौधों के अलावा बिजली के अस्थाई रूप से खंबे लगाये गये थे। इनका भी संबंधित ठेकेदार को काफी भुगतान किया गया।

अब लूट कैसे हुई। 21,33,889 रुपये के बिजली के काम कराये। सामान के अलावा इसमें 8.53 लाख रुपये स्टालेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग व लेंडिंग ओव्हर का दिया जाना बताया गया। आई.सी.टी. का भुगतान 2.08 करोड़ का किया गया, इसमें 83.54 लाख रुपये का भुगतान इन मदों में कैसे कर दिया गया इसके लिये उपयंत्री से लगाकर तमाम अधिकारी दोषी हैं। फायर फाईटिंग के काम पर 1.06 करोड़ रुपये

इसी एमबी के पृष्ठ क्रमांक 23 पर फायबर और प्लास्टिक के समुद्र मंथन की मूर्ति के बिल 1.82 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया। इसी एम.बी. के पृष्ठ क्रमांक 29 पर बांसी पहारपुरा सेंड स्टोन पिलर का भुगतान 2.54 लाख रुपयों का

का भुगतान कराया गया, जिसमें 42.40 लाख का भुगतान इन मदों में कैसे किया गया? महाकाल लोक में 09 मीटर के खम्बों का भुगतान 13.01 लाख रुपये कराया गया, जिसमें 5.20 लाख रुपयों का भुगतान इन मदों में कराया गया। 44.40 लाख रुपया मेजरमेंट बुक यानि एम.बी. के पृष्ठ क्रमांक 71 पर भुगतान करना बताया जिसमें 40 प्रतिशत भुगतान इन मदों में करीब 17.76 लाख रुपये का भुगतान कराया गया। करोड़ों रुपयों का कमीशन का भुगतान ठेकेदार को कैसे कर दिया गया इसके लिये तमाम जिम्मेदार दोषी हैं। प्लंबिंग का कार्य मेजरमेंट बुक के पृष्ठ क्रमांक 46 पर कराया, जिसका भुगतान 35.50 लाख रुपयों का कराया गया। इसमें भी सप्लाय का बिल 60 प्रतिशत व अन्य मदों में 40 प्रतिशत कमीशन दिया गया। एम.बी. के पृष्ठ क्रमांक 23 के अनुसार समुद्र मंथन का भुगतान 1.82 करोड़ रुपया कैसे दिया गया। शिव स्तम्भ मात्र 12 फीट का है उसका भुगतान 17 लाख रुपया कराया गया। जहाँ गिट्टी का भराव 8 इंच का होना था वहाँ 06 इंच भराव कराया गया। महाकाल लोक के लोकार्पण के खर्च के तमाम भुगतान भोपाल से कराये गए हैं। उसमें करोड़ों की हेराफेरी है। प्रधानमंत्री की सभा का डोम का भुगतान 16 करोड़ रुपया का हुआ। भीड़ इकट्ठी करने के लिये कई जुगत बिठाई गई। उनके खाने के सवा लाख पैकेट जयगुरुदेव संस्थान की तरफ से मुफ्त में दिये गये, किंतु इन्होंने खाने के भुगतान भी प्राप्त कर लिया। पत्थर के काम को पत्थर का भुगतान 20 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत भुगतान डिजाईनिंग, फिनिशिंग, फिक्सिंग और हेण्डलिंग ओव्हर के नाम पर भुगतान किये गये। भुगतान के लिये मेजरमेंट बुक (एम.बी.) में इन मदों को चढ़ाकर बिल आगे भेजने वाला सब इंजीनियर उसका अनुमोदन करने वाला सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री व तमाम भुगतान करने वाले अधिकारियों ने भारी कमीशन लिया है। इनके विरुद्ध जनधन का अपव्यय, जाली दस्तावेज बनाकर शासन से धोखाधड़ी करने, संगतमत होकर अपराध करने के लिये इनके विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। घटिया मटेरियल का उपयोग होने के कारण मूर्तियों की शक्लें बदलने लगी हैं। फर्श उखड़ने लगे हैं। लाखों के पौधे खरीदने बताये, किंतु प्रधानमंत्री के जाते ही सब गायब हैं। अधिकारियों की मनमानी का नतीजा है एक अयोग्य नितिन श्रीमाली को 65,000 रुपये प्रतिदिन में बगैर विज्ञप्ति या योग्यता की मांग किये भुगतान कराया गया है। संगीता बैस की नियुक्ति किस विज्ञप्ति या मांग के आधार पर की गई, इसे 22,000 रुपये प्रतिदिन का भुगतान कैसे हुआ? महाकाल लोक बेईमान, कमीशनखोरी का चारागाह बनता जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर इससे अछूता नहीं है। महाकाल में कुछ पण्डे, पुजारी, सेवक व अधिकारी चार से पाँच लाख रुपये रोज की हेराफेरी करते हैं।

किया गया। जहाँ मुफ्त में पौधे उपलब्ध होते हैं वहाँ ठेकेदार ने पौधों के नाम खूब लूटा।

लंताना कामरा आरेंज के पौधे 640 रुपये नग, लंताना कामरा आरेंज 135 रुपये नग,

सत्यर्णी 85 रुपये प्रति नग, शीशम 97.50 रुपये प्रति नग, क्लासिक फिश्चुला 97.50

नंदी द्वार, 190 मूर्तियां, 108 स्तंभ
महाकाल लोक परिसर में 18 फीट की आठ प्रतिमाएं

महाकाल लोक के पहले चरण का काम पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। ऐसे में लोगों के बीच इस बात को लेकर उत्सुकता है कि महाकाल लोक की खासियत क्या है। पहले इसका नाम महाकाल कॉरिडोर था। उद्घाटन से पहले इसका नाम महाकाल लोक रख दिया गया था। दो चरणों में इसका काम पूर्ण होना है। महाकाल लोक के दोनों चरणों की लागत लगभग 1150 करोड़ रुपये है। महाकाल लोक के नाइट गार्डन में भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित 190 मूर्तियां हैं। 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जिन पर भगवान शिव और उनके गणों की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। पूरे परिसर में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं। इनमें नटराज, शिव, गणेश, कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती, समुद्र मंथन दृश्य इसमें शामिल हैं। वहीं, परिसर में 23 प्रतिमाओं की ऊंचाई 15 फीट हैं। इनमें शिव नृत्य, 11 रुद्र, महेश्वर अवतार, अघोर अवतार, काल भैरव, शरभ अवतार, खंडोबा अवतार, वीरभद्र द्वारा दक्ष वध, शिव बारात, मणि भद्र, गणेश और कार्तिकेय से साथ पार्वती, सूर्य और कपालमोचक शिव शामिल हैं। 17 प्रतिमाएं 11 फीट की हैं। इनमें प्रवेश द्वार पर श्री गणेश, अर्द्धनारीश्वर, अष्ट भैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वमित्र, गौतम, कश्यप, जमदग्नी शामिल हैं। 08 प्रतिमाएं महाकाल लोक में 10 फीट की है। इनमें लेटे हुए गणेश, हनुमान शिव अवतार, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, लकुलेश, पार्वती के साथ खेलते गणेश की प्रतिमा शामिल हैं। इसके साथ ही महाकाल लोक में नौ फीट की 19 प्रतिमाएं हैं। इनमें यक्ष-यक्षिणी, सिंह, बटुक भैरव, सती, पार्वती, ऋषि भृंगी, विष्णु, नंदीकेश्वर, शिवभक्त, रावण, श्रीराम, परशुराम, अर्जुन, सती, ऋषि शुक्राचार्य, शनिदेव, ऋषि, दधिचि की प्रतिमाएं शामिल हैं। महाकाल लोक में 26 फीट ऊंचा नंदी द्वार मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसके बाद शिवमय संकुल की भी अलग खासियत है। महाकाल संकुल को पूर्णता शिवमय सजाया गया है, इसमें कमल कुंड, सप्तऋषि, मंडल, शिव स्तंभ, मुक्ताकाश रंगमंच का निर्माण प्रमुख है। पुराण प्रसिद्ध रुद्र सागर के तट विकास के साथ त्रिवेणी संग्रहालय का एकीकरण कर चारों ओर हरियाली भरा वातावरण रखा गया है। साथ में विशाल कॉरीडोर में 111 फीट लंबे संपूर्ण शिव विवाह के वृतांत को प्रदर्शित करते हुए म्यूरल पेंटिंग प्रदर्शित की गई हैं। वहीं, शिव अवतार वाटिका में भगवान शिव से जुड़ी कथाएं और विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई है। त्रिपुरारी महाकाल- महाकाल संकुल में भव्य मूर्ति शिल्प स्थापित की गई है। इसमें स्वयं ब्रह्मा जी रथ के सारथी हैं। यह संदेश देती है कि अधर्म पर सदैव ही धर्म की विजय होती है। वहीं, कैलाश पर्वत और रावण साधना को भी दिखाया गया है। इसमें असुरराज रावण ने कठोर तप करके महादेव को प्रसन्न किया था। इस प्रसंग को भी प्रतिमा में दर्शाया गया है। नृत्य करते गजानन को भी दिखाया गया है। मौन साधना करते सप्तऋषि की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही महाकाल मंदिर रुद्र सागर के तट पर है। यह सरोवर उज्जैन के सात सरोवरों में से प्रमुख है, अब इसमें श्रद्धालु नौका विहार का आनंद भी ले सकेंगे। संहारक महादेव की प्रतिमा भी यहां स्थापित की गई है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। महाकाल प्रांगण में 108 विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। इन पर महादेव के परिवार के चित्र उकेरे गए हैं। यह चित्र भी प्रतिमा के स्वरूप बने हैं और इनमें शिव, शक्ति, कार्तिकेय और गणेश की लीलाओं का वर्णन है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में सुगमता के लिए 900 मीटर लंबा महाकालेश्वर पथ बना है, यहां से भक्त पैदल और वोल्फ कोर्ट से जा सकेंगे। परिसर के अंदर एक सर्व सुरक्षित संकुल का निर्माण किया गया है। इससे महाकाल मंदिर में जाने वालों की निगरानी के लिए वॉच टॉवर स्थापित किया गया है। मूर्तियां स्वयं इतिहास की जानकारी देंगी। इसके लिए आपको बारकोड को स्कैन करना होगा।

प्रति नग, परिजात का पौधा 97.50 रुपये प्रति नग, आम 260 रुपये प्रति पौधा, जामुन 187 रुपये प्रति पौधा, गुलर 195 रुपये प्रति पौधा, अफ्रीकन टूलीप 195 रुपये प्रति पौधे खरीदे गए। अब ये पौधे गायब हैं। बिलों के भुगतान हो गये। किसी

महाकाल मंदिर की कमाई का अन्य आयोजनों में खर्च

मप्र जन अभियान परिषद् के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय को महाकाल प्रबंध समिति का सदस्य बना दिया था, जिसने महाकाल को भ्रष्टाचार, हेराफेरी का अड्डा बना दिया था। इसके समय में जितने सेवक महाकाल में रखे उनसे इसने मोटी रिश्वत वसूली। इसके काल में धर्मादे की राशि का भारी दुरुपयोग हुआ। उपाध्याय जब परिषद के उपाध्यक्ष बने तो इन्होंने फिर से महाकाल की धर्मादे की रकम पर डाका डालना शुरु कर दिया। विभाष उपाध्याय जब महाकाल प्रबंध समिति के नामजद सदस्य थे तो इन्होंने यहाँ की खरीदी, निर्माण व सेवकों की नियुक्ति में खूब कमीशनखोरी की। शैव महोत्सव, नमामि देवि नर्मदे व एकात्म यात्रा के आयोजन महाकाल से शुरु कराये गये। इनमें करोड़ों की कमीशनखोरी की। मंदिर समिति द्वारा एक से तीन जनवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय शैव महोत्सव का आयोजन किया गया, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैवमत के विद्वानों को बुलाया गया इसमें शासन और महाकाल मंदिर ने पांच करोड़ रुपये खर्च किया। इस वर्ष चुनाव थे इसलिये और इससे पूर्व 30 दिसम्बर से संघ प्रमुख एक सप्ताह के लिये उज्जैन प्रवास पर थे। इसलिये उनके इशारों पर शैव महोत्सव का आयोजन किया गया। फिर आदि शंकराचार्य के नाम पर एकात्म यात्रा निकाली गई, जिसका

भुगतान का भौतिक के सत्यापन नहीं कराया गया।

महाकाल लोक के दूसरे चरण में ये होगा

महाराजवाड़ा परिसर का उन्नयन व हैरिटेज धर्मशाला के पुनरउपयोग, महाराजवाड़ा बेसमेंट पार्किंग व वेण्डर क्षेत्र निर्माण, नीलकंठ वन मार्ग विकास, नीलकंठ वन विकास, रूद्र सागर

अनुमानित खर्चा था दस करोड़ रुपया। तभी भारत माता मंदिर और भक्त निवास का उद्‌घाटन होना था उसका भी खर्च का बड़ा हिस्सा महाकाल समिति द्वारा किया गया। नमामि देवि नर्मदे यात्रा में उज्जैन से भीड़ के रुप में लाने ले जाने के लिये कार, टैक्सी, बसों का किराया, नाश्ता, खाना आदि के खर्च के भुगतान से जिला पंचायत द्वारा मना करने पर नगर निगम परिषद् ने प्रस्ताव पास कर तमाम जाली बिलों के भुगतान नगर निगम उज्जैन से कराये। दिसम्बर 2022 में फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत का आगमन हुआ तो उनके लिये जन अभियान परिषद् व दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा सांवेर रोड स्थित मालगुडी डेज में जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके नाम का जल स्तम्भ का निर्माण करवाकर महाकाल में उसका उद्‌घाटन कराया गया, महाकाल मंदिर समिति द्वारा इसके निर्माण के लिये साठ किलो चांदी दी गई और उसकी मजदूरी भी महाकाल समिति द्वारा की गई एवं आयोजन का तमाम खर्च मंदिर समिति द्वारा उठाया गया। इस तरह करीब एक करोड़ रुपयों से ज्यादा का खर्च धर्मादे के धन से किया गया। महाकाल में बगैर किसी योजना के करोड़ों के खर्च हो रहे हैं। महाकाल लोक में आ रहे भक्तों की संख्या की आड़ में मंदिर समिति के भ्रष्टाचारी अपनी जेबें भर रहे हैं।

पुनरूद्धार, छोटा रुद्र सागर लेकफ्रंट निर्माण, रुद्र सागर पर पैदल पुल, शिखर दर्शन, आपातकालीन प्रवेश व निर्गम मार्ग, लेजर और वाटर स्क्रीन शो, श्री महाकालेश्वर मन्दिर में भूमिगत प्रतीक्षालय, मन्दिर परिसर का फसाड, आन्तरिक परिसर का विकास, नन्दी हॉल का सौंदर्यीकरण, महाकालेश्वर मन्दिर परिसर में महाराजवाड़ा परिसर का सम्मिलन, श्री

महाकाल लोक के भ्रष्टाचार के असली गुनहगार भूपेन्द्र सिंह!

मध्यप्रदेश सरकार में नगरी प्रशासन और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री है। इनकी ही देखरेख में उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण किया गया है। निर्माण के समय कई बार भूपेन्द्र सिंह ने कार्यो का निरीक्षण भी किया। कह सकते हैं कि इन्हें पता था कि निर्माण कार्य किस स्तर के हो रहे हैं और क्या खेल चल रहा है, लेकिन भूपेन्द्र सिंह ने आज तक इस पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन आज जिस तरह से महाकाल लोक की धांधलिया और भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं तो भूपेन्द्र सिंह प्रथम दृष्टि में कठघरे में है। यह अपनी जिम्मेदारी से किनारा नहीं कर सकते। महाकाल लोक के पूरे भ्रष्टाचार में भूपेन्द्र सिंह असली गुनहगार है। इसके लिए भूपेन्द्र सिंह बच नहीं सकते। महाकाल लोक के मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुये भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि महाकाल लोक में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जबकि सारी दुनिया ने देखा है कि लोक में बनी सप्तऋषियों की 7 में से 6 मूर्तियां मामूली हवा में ही धरासायी हो गई। मीडिया के सामने उन्होंने खुद को और सरकार एवं निर्माण एजेंसी को बचाने की पूरी कोशिश की। अब जबकि सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। आज जब भ्रष्टाचार में जिन अधिकारियों या निर्माण एजेंसियों के नाम सामने आ रहे है वह तो केवल मोहरे भर है। असली मास्टर माइंड भूपेन्द्र सिंह ही है जिन्होंने निश्चित तौर पर कमीशनखोरी की होगी। क्योंकि इनका इतिहास रहा है कि यह अपने विभाग में होने वाले हर एक कार्यो में कमीशन खोरी करते हैं।

महाकाल लोक स्थित स्टेच्यू प्लांटर का संरक्षण, मन्दिर पहुंचने के लिए चार सुगम मार्ग, हरिफाटक पार्किंग, सीसीटीवी निगरानी व एक्सेस नियंत्रण प्रणाली, रामघाट का सौंदर्यीकरण, त्रिवेणी संग्रहालय का विस्तार, दान द्वारा धर्मशाला व अन्नक्षेत्र का निर्माण, उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मन्दिर तक रोप-वे, पुलिस थाना व पुलिस क्वाटर का विस्थापन, त्रिवेणी संग्रहालय के सामने पार्किंग भोजनशाला का विस्तार। कार्यो की लागत 778 करोड़ रुपए है। महाकाल परिसर का निर्माण 20 हेक्टेयर में किया जा रहा है। ये उत्तरप्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से चार गुना बड़ा है, जो पांच हेक्टेयर में फैला है।

चीतों की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार

प्रमोद भार्गव

अफ्रीकी देशों से लाकर कूनो अभ्यारण्य में बसाए गए चीतों की लगातार हो रही मौतों से उनकी निगरानी, स्वास्थ्य और मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेबार है? यह सवाल बड़ा होता जा रहा है। जिस तरह से चीते अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं, उससे लगता है उच्च वनाधिकारियों का ज्ञान चीतों के प्राकृतिक व्यवहार से लगभग अछूता है। इसलिए एक-एक कर तीन वयस्क और तीन शावकों की मौत चार माह के भीतर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी चीता परियोजना के लिए यह बड़ा झटका है। विडंबना है कि इन चीतों की वास्तविक मौत के कारण भी पता नहीं चले हैं। 23 मई 2023 को जिस चीता शावक की मौत हुई थी, उसे जन्म से ही कमजोर बताया जा रहा था। मां का दूध भी वह कम पी रहा था। बावजूद उसके इलाज के ठोस प्रयास नहीं हुए। इलाज भी तब शुरू हुआ जब निढाल होकर वह गिर गया और निगरानी दल ने चिकित्सकों को जानकारी दी। हैरानी है कि इन चीतों की निगरानी भारतीय विशेषज्ञों के साथ दो नामीबिया के और चार दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञ कूनो में डेरा डाले हुए हैं। क्या इनकी जिम्मेबारी नहीं थी कि वे इस बीमार शावक द्वारा दूध नहीं पीने के कारण को जानते और उपचार करते। इसी तरह दो शावक और मर गए। जो चौथा शावक जीवित है, उसकी हालत भी ठीक नहीं है। उसे बकरी का दूध पिलाया जा रहा है। जबकि बकरी का दूध डेंगू जैसे बुखार की स्थिति में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दिया जाता है। शावकों की मौतों पर पर्दा डालने के लिए बताया जा रहा है कि चीता शावकों की मृत्यु दर बिल्ली प्रजाति के प्राणियों में सबसे ज्यादा है। इसलिए इन मौतों को अनहोनी नहीं माना जाना चाहिए। सवाल है कि चार में से तीन शावक मर गए तो यह दर 75 फीसदी पर पहुंच गई। चौथा शावक भी जीवन और मृत्यु की अंजानी कड़ियों में झूल रहा है। तब यह स्थिति असामान्य क्यों नहीं है? साफ है इनका जीवन बचाने में लापरवाही बरती गई। 09 मई को मादा चीता दक्षा की मौत से यह स्पष्ट है कि वन्य प्राणी विशेषज्ञों को व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। दक्षा से जोड़ा बनाने के लिए एक साथ दो नर चीते छोड़ दिए गए, जो एक बड़ी भूल थी। बिल्ली प्रजाति के नर प्राणियों में मादा से संबंध बनाने को लेकर संघर्ष और मौत आम बात है। बावजूद इनकी निगरानी नहीं की गई। इसी का परिणाम रहा कि इस जानलेवा हमले की खबर प्रबंधन को तब

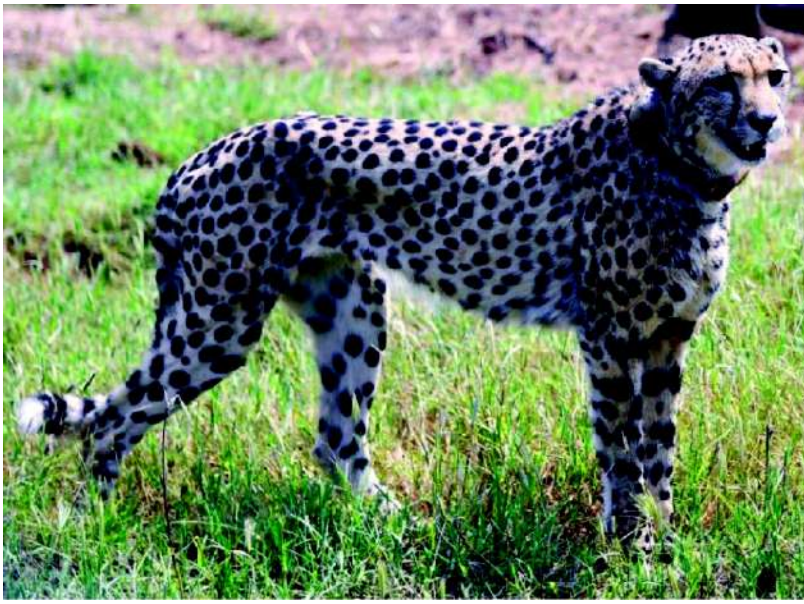

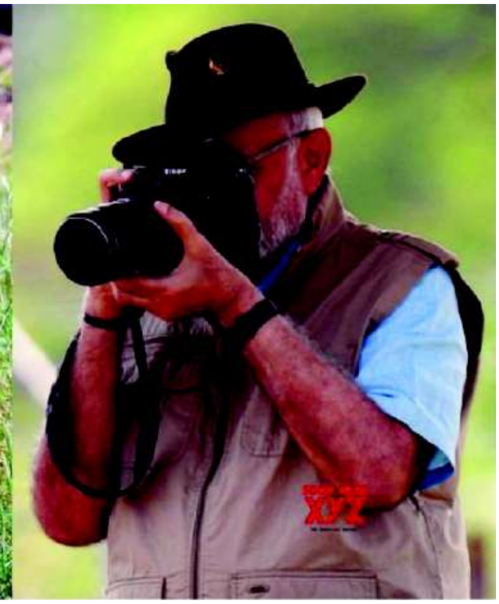

लगी, जब दक्षा को बचाने के प्रयास असंभव हो गए। आश्चर्य इस बात पर भी है कि जब प्रत्येक चीता के गले में कालर आईडी है और चीते बाड़ों में कैमरों की निगरानी में हैं, फिर भी यह चूक हुई तो कहा जा सकता है कि ईमानदारी से निगरानी की ही नहीं जा रही है। 25 अप्रैल को उदय नाम के चीते की मृत्यु हुई। इस मौत को हृदयाघात बताया गया। लेकिन सब विच्छेदन के बाद मौत का कारण संक्रमण निकला। उदय की खस्ता हालत का भी तब पता चला जब वह निढाल होकर एक ही जगह पड़ा रहा। 27 मार्च को 20 चीतों में से कूनो में सबसे पहले मादा साशा की मौत की खबर आई थी। इसकी मौत का कारण गुर्दा में संक्रमण बताया गया। यह गंभीर बीमारी नामीबिया से ही थी। यह जानकारी नामीबिया में ही भारतीय वनाधिकारियों को दे दी गई थी। बावजूद इसे लाया तो गया, लेकिन इलाज का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया। आखिर बीमार चीता लाने की क्या मजबूरी थी, वन प्रबंधन इस प्रश्न पर मौत के बाद से ही चुप्पी साधे हुए है, क्यों? इन मौतों से यह आशंका प्रबल हो रही है कि 24 में से छह चीते चार माह में मर गए, तब इस परियोजना का भविष्य क्या होगा? यदि इन मौतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और निगरानी के पुख्ता प्रबंध नहीं हुए तो कहीं हम 75 साल पहले निर्मित

यदि अतीत में जाएं तो पता चलता है कि विदेशी चीतों को भारत की धरती कभी रास नहीं आई। इनको बसाने के प्रयास पहले भी होते रहे हैं। एक समय चीते की रफ्तार भारतीय वनों की षान हुआ करती थी। लेकिन 1947 के आते-आते चीतों की आबादी पूरी तरह लुप्त हो गई।

हुई चीतों के संदर्भ में शून्य स्थिति पर न पहुंच जाएं? क्योंकि जो धरती चीतों से गुलजार थी, उस पर 1947 में विराम लग गया था।

दरअसल यदि अतीत में जाएं तो पता चलता है कि विदेशी चीतों को भारत की धरती कभी रास नहीं आई। इनको बसाने के प्रयास पहले भी होते रहे हैं। एक समय चीते की रफ्तार भारतीय वनों की षान हुआ करती थी। लेकिन 1947 के आते-आते चीतों की आबादी पूरी तरह लुप्त हो गई। 1948 में अंतिम चीता छत्तीसगढ़ के सरगुजा में देखा गया था। जिसे मार गिराया गया। चीता तेज रफ्तार का आश्चर्यजनक चमत्कार माना जाता है। अपनी विशिष्ट एवं लोचपूर्ण देहयष्टि के लिए भी इस हिंसक वन्य जीव की अलग पहचान थी। शरीर में इसी चपलता के कारण यह जंगली प्राणियों में सबसे तेज दौड़ने वाला धावक है। इसलिए इसे जंगल की बिजली भी कहा गया। हालांकि भारत में चीतों के पुनर्वास की कोशिशें असफल रही हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से 1993 में दिल्ली के चिड़िया घर में चार चीते लाए गए थे, लेकिन छह माह के भीतर ही ये चारों मर गए। चिड़ियाघर में इनके आवास, परवरिश व प्रजनन के पर्याप्त उपाय किये गये थे, लिहाजा उम्मीद थी कि यदि इनकी वंशवृद्धि होती है तो देश के अन्य चिड़िया घरों व

अभ्यारण्यों में ये चीते स्थानांतरित किये जाएंगे। हालांकि चीतों द्वारा चिड़ियाघरों में प्रजनन अपवाद घटना ही होती है। नतीजतन प्रजनन संभव होने से पहले ही चीते मर गए।

बीती सदी में चीतों की संख्या एक लाख तक थी, लेकिन अफ्रीका के खुले घास वाले जंगलों से लेकर भारत सहित लगभग सभी एशियाई देशों में पाया जाने वाला चीता अब पूरे एशियाई जंगलों में गिनती के रह गए हैं। राजा चीता (एसिनोनिक्स रेक्स) जिम्बाब्वे में मिलता है। अफ्रीका के जंगलों में भी गिने-चुने चीते रह गए हैं। तंजानिया के सेरेंगती राष्ट्रीय उद्यान और नामीबिया के जंगलों में गिने-चुने चीते हैं। प्रजनन के तमाम आधुनिक व वैज्ञानिक उपायों के बावजूद जंगल की इस फुर्तीली नस्ल की संख्या बढ़ाई नहीं जा पा रही है। यह प्रकृति के समक्ष वैज्ञानिक दंभ की नाकामी है।

जूलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन की रिपोर्ट को मानें तो दुनिया में 91 प्रतिशत चीते 1991 में ही समाप्त हो गए थे। अब केवल 7100 चीते पूरी दुनिया में बचे हैं।

जूलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन की रिपोर्ट को मानें तो दुनिया में 91 प्रतिशत चीते 1991 में ही समाप्त हो गए थे। अब केवल 7100 चीते पूरी दुनिया में बचे हैं।

एशिया के ईरान में केवल 50 चीते शेष हैं। अफ्रीकी देश केन्या के मासीमारा क्षेत्र को चीतों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब इनकी संख्या गिनती की रह गई है। बीती सदी के पांचवे दशक तक चीते अमेरिका के चिड़ियाघरों में भी थे। प्राणी विशेषज्ञों की अनेक कोशिशों के बाद इन चीतों ने 1956 में शिशुओं को जन्म भी दिया, परंतु किसी भी शिशु को बचाया नहीं जा सका। चीते द्वारा किसी चिड़ियाघर में जोड़ा बनाने की यह पहली घटना थी, जो नाकाम रही। जंगल के हिंसक जीवों का प्रजनन चिड़ियाघरों में आश्चर्यजनक ढंग से प्रभावित होता है, इसलिए शेर, बाघ, तेंदुए व चीते चिड़ियाघरों में जोड़ा बनाने की इच्छा नहीं रखते हैं। भारत में चीतों की अंतिम पीढ़ी के कुछ सदस्य बस्तर-सरगुजा के घने जंगलों में थे, जिन्हें 1947 में देखा गया था। इनके संरक्षण के जरूरी उपाय हो

पाते, इससे पहले ही चीतों के इन अंतिम वंशजों का शिकार, षिकार के शौकीन राजा-महाराजाओं ने करके वन की इस तेज गति के ताबूत में अंतिम कील ठोंक दी। इस तरह भारतीय चीतों की नस्ल पर पूर्ण विराम लग गया था।

हमारे देश के राजा-महाराजाओं को घोड़ों और कुत्तों की तरह चीते पालने का भी शौक था। चीता शावकों को पालकर इनसे जंगल में शिकार कराया जाता था। राजा लोग जब जंगल में आखेट के लिए जाते थे, तो प्रशिक्षित चीतों को बैलगाड़ी में बिठाकर साथ ले जाते थे। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी, जिससे यह किसी मामूली वन्य जीव पर न झपटे। जब शिकार राजाओं की दृष्टि के दायरे में आ जाता था, तो चीते की आंखों की पट्टी खोलकर शिकार की दिशा में हाथ से इशारा कर दिया जाता था। पलक झपकते ही शिकार चीते के जबड़े में होता। शिकार का यह अद्‌भुत करिश्मा देखना भी एक आश्चर्यजनक रोमांच की बात रही होगी ? भारत के कई राजमहलों में पालतू चीतों से शिकार कराने के अनेक चित्र अंकित हैं। मुगल काल में अकबर ने सैंकड़ों चीतों को बंधक बनाकर पाला। मध्यप्रदेश में मांडू विजय से लौटने के बाद अकबर ने चंदेरी और नरवर (शिवपुरी) के जंगलों में चीतों से वन्य प्राणियों का शिकार किया। नरवर के जंगलों में अकबर ने जंगली हाथियों का भी खूब शिकार किया। ग्वालियर रियासत में सिंधिया राजाओं ने भी चीते पाले हुए थे, लेकिन चीतों को पाले जाने का शगल ग्वालियर रियासत में बीसवीं सदी के अंत तक ही संभव रहा। मार्को पोलो ने तेरहवीं शताब्दी के एक दस्तावेज का उदाहरण देते हुए बताया है कि कुबलई खान ने अपने ठिकानों पर एक हजार से भी अधिक चीते पाल रखे थे। इन चीतों के लिए अलग-अलग अस्तबल थे। चीते इस पड़ाव की चैकीदारी भी करते थे। बड़ी संख्या में चीतों को पालतू बनाने से इनके प्रकृतिजन्य स्वभाव पर प्रतिकूल असर तो पड़ा ही, इनकी प्रजनन यिाओं पर भी बेहद प्रतिकूल असर पड़ा। गुलामी की जिंदगी गुजारने व सईस के हंटर की फटकार की दहशत ने इन्हें मानसिक रूप से दुर्बल बना दिया, जिससे चीतों ने विभिन्न शारीरिक यिाओं में रुचि लेना बन्द कर दिया। जब चाहे तब भेड़-बकरियों की तरह हांक लगा देने से भी इनकी सहजता प्रभावित हुई। चीतों की ताकत में कमी न आए इसके लिए इन्हें मादाओं से अलग रखा जाता था। बैलों की तरह नर चीतों को बधिया करने की क्रूरताएं भी राजा-महाराजाओं ने खूब अपनाईं। इन सब कारणों से जंगल की इस बिजली की रोषनी मंद पड़ती गई और इक्कीसवीं शताब्दी के मध्य के आसपास एशिया भर में बुझ भी गई। कूनो में चीतों की जरूरत से यादा तकनीक आधारित निगरानी भी इनकी मौत का कारण बन रही है।

पहाड़ों के जंगलों में आग

प्रशांत सिन्हा

भारत में मार्च के पहले 12 दिनों में जंगल की आग में 115 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी। भारत के वन सर्वेक्षण द्वारा सैटेलाइट आधारित वन अग्नि निगरानी के अनुसार, 1 मार्च से 12 मार्च के बीच लगभग 42,799 जंगल की आग का पता चला है। यह संख्या पिछले साल 19,929 से अधिक है। मार्च में एफएसएल द्वारा 772 बड़े जंगल की आग की सूचना दी गई थी, जिनमें से 202 ओडिशा में, 101 मिजोरम में, 43 असम में, 21 महाराष्ट्र में, 61 छत्तीसगढ़ में और 48 आंध्र प्रदेश में थीं। जंगलों में आग का सबसे बड़ा कारण कम बारिश, गर्मी और सुखी मिट्टी होती है। इसी साल के मार्च में अत्यधिक गर्मी के कारण पश्चिमी राज्यों से जंगल में आग लगने की खबरें आई थीं। गोवा, महाराष्ट्र के कोंकण भागों में लू जैसी स्थिति देखी जा रही थी। अभी पिछले हफ़्ते से गर्मी बढ़ने के साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। वैसे यहां बताना ज़रूरी है कि उत्तराखंड में 15 फरवरी से 15 जून तक का समय फायर सीजन कहलाता है। ऐसे में जंगलों की आग की घटनाएं सबसे यादा देखने को मिलती है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी इलाकों में मौसम बारिश के कारण ठंडा बना हुआ था। जिससे आग की घटनाएं कम हो रही थीं। लेकिन मैदानी

इलाकों में तापमान बढ़ने के साथ वन विभाग की चिंता भी बढ़ रहीं है। आग लगने से तापमान में बढ़ोतरी तो होती ही है पर्यावरण के साथ साथ मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। प्राकृतिक जल श्रोत, नदी, पशु पक्षी, वन्य जीव कोई भी जंगलों की आग से नही बच सका है। उत्तराखंड में आग लगने की यह कोई नई बात नही है। यह तो हर साल होने वाली त्रासदी है जिसके वजह से लाखों हेक्टेयर जंगल आग में स्वाहा हो जाते हैं। इसमें लाखों पशु पक्षी, कीट पतंग के आवास नष्ट हो जाते हैं। उत्तराखंड में यह त्रासदी स्थाई त्रासदी है। वन अधिकारी इसे रोकने की प्रयास करते हैं लेकिन वह नाकाफी सिद्ध हुआ है। इसकी विस्तार से पड़ताल की जाए तो इसकी जड़ में उपेक्षा नजर आती है। देहरादून में स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने देश भर में लगने वाली आग की सूचना देने की एक प्रणाली विकसित की है। इसकी मदद से जंगल में कहीं भी आग लगने के चार घंटे के अन्दर अपने आप ही उस इलाके में तैनात डीएफओ के मोबाइल पर इसकी सूचना आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद आग की घटना पर रोक नहीं लग पाना दर्शाता है कि लोगों में कितनी लापरवाही है।

प्राकृतिक जल श्रोत, नदी, पशु पक्षी, वन्य जीव कोई भी जंगलों की आग से नही बच सका है। उत्तराखंड में आग लगने की यह कोई नई बात नही है। यह तो हर साल होने वाली त्रासदी है जिसके वजह से लाखों हेक्टेयर जंगल आग में स्वाहा हो जाते हैं।

उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं दोनों के पहाड़ों के जंगलों में आग लगती है। राज्य का लगभग 45 फीसदी भाग वनों से ढका हुआ है और यह हिमालय के दक्षिणी ढलान पर स्थित है, जहां इस राज्य को बड़ी मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है।, जिससे अधिक ताप होता है। लेकिन उत्तराखंड को अपने प्राकृतिक संसाधनों के अत्याधिक दोहन, पर्यटन और इसके

जंगलों की बनावट में बदलाव का भी सामना करना पड़ा है। 2002 और 2021 के बीच उत्तराखंड ने 17,900 हेक्टेयर वृक्षों के क्षेत्र खो दिए। अकेले 2021 में राय ने 820 हैक्टेयर प्राकृतिक वन खो दिए, जो 428 किलो टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बराबर है। इससे वन संपदा और जैव विविधता का खात्मा हुआ है। जिसका कोई आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। महज चार वर्षो में जंगलों की आग से उत्तराखंड में तीन गुना से भी अधिक की क्षति हुई है। जंगल में पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंग, पक्षियों की ऐसी दुनिया होती है जिसमें कोई भी अनहोनी पूरे तंत्र को क्षत विक्षप्त कर देती है। जंगल की आग से मिट्टी पानी, वनोपज आदि सभी पर व्यापक असर पड़ता है। हमारी वन नीति के चलते गांव वासियों - वन वासियों का वनों से जो रिश्ता था वह अब खत्म हो गया है। सरकार द्धारा संचालित वन जागरुकता अभियान गांव, गांव वासियों और जंगल में रहने वाले वन वासियों को जंगलों से जोड़ने में नाकाम रहा है। जंगल की आग का पर्यावरणीय प्रभाव, वैश्विक तापमान में उसकी भुमिका के अलावा कई अन्य मामलों में भी अधिक गंभीर है। जब जंगल जलते हैं तो वे पार्टिकुलेट मैटर छोड़ते हैं। हवा में पार्टिकुलेट मैटर या एयरोसोल बढ़ने से बारिश की बूंदों के आकार में वृद्धि होती है जिससे बादल फटते हैं। जितना अधिक पार्टिकुलेट मैटर होता है, बारिश की गड़बड़ी की संभावना उतनी ही अधिक होती है, जिससे बादल फटते हैं, जिससे राय प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। बादलों में पार्टिकुलेट मैटर की उपस्थिति काफी लंबे समय तक शुष्क काल को बढ़ाती है। इस प्रकार हीटवेव और जंगल की आग का एक दुष्च पैदा होता है। एक अध्ययन से पुष्टि हुई है कि पार्टिकुलेट मैटर, गलेशियर के पिघलने के प्रमुख कारणों में से एक है। एक अध्ययन सबूत है कि दुनिया में जंगलों में आग की यही रफ्तार रही तो 2100 तक समूची दुनिया से जंगलों का नाम ही मिट जाएगा। इस आग से सबक लेने की जरूरत है। वन विभाग को पहले से चौकस होना पड़ेगा और लोगों की भागीदारी और लगाव जंगलों के प्रति बढ़ाना होगा। तभी ऐसी आपदाओं को वक्त रहते टाला जा सकेगा।

मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन?

रघु ठाकुर

मणिपुर में मैतेई समाज को आदिवासी समाज में शामिल करने के विरोध में स्थानीय आदिवासियों में जिनमें नगा और कुकी मुख्यतः शामिल है, ने तीखी और हिंसक प्रतिक्रिया की है जो कि वहां की सरकार के लिये भी अप्रत्याशित थी। हालांकि मैतई समाज को आदिवासी समाज में शामिल करने का आदेश सरकार ने ही दिया था और मुख्यमंत्री वीरेन्द्र सिंह की इसमें अहम भूमिका थी। चूंकि मैतई समाज की आबादी राज्य की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत है इसलिये मुख्यमंत्री ने इसे अपने चुनाव जीतने का एक महत्वपूर्ण हथियार माना होगा। हालाकि हाल ही में जब इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की और कहा कि हाईकोर्ट का राज्य सरकार को दिया गया आदेश गलत है। इस घटना में जहां एक तरफ 100 से अधिक लोग मारे गये लगभग 15000 लोग निर्वासित हुये जिन्हें सेना ने दंगाग्रस्त इलाकों से निकाला और 500 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुये। सार्वजनिक सम्पत्ति की और जन धन की कितनी हानि हुई है इसकी कल्पना करना कठिन है। आखिर ऐसी घटनाओं के लिये कौन जिम्मेदार है इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिये। मेरी राय में इस घटना के लिये तीनों पक्ष जवाबदार हैं।

1- न्यायपालिका याने हाईकोर्ट

2- राज्य सरकार

3- मैतई समाज के अगुआ लोग

जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि हाईकोर्ट का आदेश या निर्देश कितना अविचारित था इसका तो संकेत अपनी सार्वजनिक टिप्पणी के माध्यम से स्वतः सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है। आजकल शीर्ष अदालतों को रोज याचिका के नाम से अपनी मनमर्जी की टिप्पणियां करनाए शब्द क्रान्तिकारिता बखान करना एक चलन सा बन गया और इस बुराई को स्वतः शीर्ष अदालतें और उनके संजीदा जज भी महसूस करने लगे हैं। अभी हाल में अप्रैल 23 को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जे.

चेलमेस्वर ने केरल के कोच्चि में क्या कोलिजियम संविधान से अलग है। विषय पर बोलते हुये कहा कि कोलिजियम के सामने तमाम मामले आते हैं। याने शीर्ष न्यायपालिका की नियुक्ति और उसके प्रत्याशी जजों के बारे में सारे तथ्य कोलेजियम के सामने प्रस्तुत होते हैं। स्वतः ऐसे जजों के विरूद्ध कोलेजियम को कार्यवाही भी करना चाहिए। निःसंदेह श्री चेलमेश्वर की पीड़ा एक सच्चे इंसान की पीड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस जज पर आरोप होते हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती और बहुत हुआ तो उसका तबादला कर बात खत्म हो जाती है। उन्होंने चयन प्रक्रियाए कार्यवाही करने के तरीके को कटघरे में खड़ा किया है। यह सही भी है। केवल एक जस्टिस कर्णन जो बंगाल हाईकोर्ट के जज थे को छोड़कर किसी और जज के विरूद्ध कोई कार्यवाही हुई हो कम से कम मुझे तो याद यही है। और वह भी शायद इसलिये विवश होकर करना पड़ी कि

चेलमेश्वर कहते है कि जो तथ्य प्रस्तुत होते हैं। उनके आधार पर कोलेजियम कोई कार्यवाही नहीं करता। मान लिया कोलेजियम जजों के चयन के लिये गठित एक मान्य संस्था है। परन्तु अगर चयन की प्रत्याशी वाले न्यायाधीशों के विरूद्ध कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिनमें वह दोषी हैं तो उन्हें केवल आपात्र मानकर खारिज कर देना उचित नहीं है। जस्टिस चेलमेश्वर कहते हैं कि उन सूचनाओं के आधार पर यह भी कहा कि मैं राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने का समर्थक नहीं हूँ परन्तु कोलेजियम व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए ताकि उसका लाभ आम आदमी को मिले यह उनकी चिंता है। उन्होंने कहा कि कई जज तो इतने आलसी होते हैं कि उन्हें फैसले लिखने में सालों लग जाते हैं। और कुछ ऐसे है कि उन्हें काम नहीं आता है। अपने सधे व संतुलित शब्दों में जेण चेलमेश्वर ने संपूर्ण न्यायपालिका उसकी कर्णन ने अपनी संवैधानिक और नैतिक सभी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया था। और वह तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ ही न केवल आदेश बल्कि सम्मन व वारेन्ट जारी करने लगे थे। यानी एक प्रकार से वे न्यायिक अराजकता या संवैधानिक अराजकता कर रहे थे।

अगर मणिपुर के हाईकोर्ट ने मैतई समाज को आदिवासी समाज में शामिल करने की याचिका को बजाय सरकार को

निर्देश करने के प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया होता तो सरकार शायद यह कदम नहीं उठाती।

हालांकि न्यायपालिका के असंवैधानिक निर्देश से मणिपुर की सरकार और मुख्यमंत्री भी दोषमुक्त नहीं हो सकते क्योंकि जन भावनाओं को समझना कानून व्यवस्था को संभालना समाज के व्यापक हित में न्याय संगत फैसला लेना यह सरकार का मूल दायित्व होता है। इसके पहले भी देश में कई स्थानों पर ऐसी आरक्षण की मांगे हुई है जो तार्किक व वैधानिक नहीं थी और वहां कि सरकारों ने विरोध सहकर भी ऐसे जन आंदोलनों का मुकाबला किया है। राजस्थान में गुर्जर समाज ने भी आदिवासियों में शामिल करने की मांग को लेकर भारी आंदोलन किया था जिसमें काफी लोग मारे गये थे। परन्तु न्यायपालिका या राज्य सरकार ने विरोध सहकर भी उसे लागू नहीं किया। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री वीरेन्द्र सिंह को देश की इस अहम घटना की जानकारी कैसे नहीं थी या फिर 53 प्रतिशत की बहुमत आबादी के समर्थन के लालच में वे होश व हवास खो बैठे। उनके एक निर्णय से कितने जनधन की हानि हुई वह एक जगह है और दूसरे प्रदेश में जो जातीय वैमनस्यता बनी है वह भी मुख्यमंत्री जी का क्ष य अपराध नहीं है।

आजकल जातीय समूहों में यह होड़ लगी है कि वह कैसे फौरी लाभ उठायें और समस्याओं के बड़े हल के लिये वे कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहते। व्यवस्था को बदलकर कोई नई व्यवस्था नहीं लाना चाहते बल्कि छोटे लक्ष्यों को लेकर लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। आजादी के बाद राजस्थान में मीणा समाज को आदिवासियों में शामिल किया गया था। राजस्थान के मूल आदिवासी गौड़ भील आदि उस समय बिलकुल ही अशिक्षित थे व जंगलों में थे इसलिये कुछ दशकों तक अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण का सर्वाधिक लाभ या कहें स पूर्ण लाभ मीणा समाज ने उठाया। एक-एक घर में कई-कई आईएएस आईपीएस व बड़े पदों वाले हो गये। उनका सामना उन कमजोर आदिवासियों से था जो वास्तव में आदिवासी है परन्तु शिक्षा में बहुत पीछे हैं। उनमें इतनी जाग्रति और संगठन भी नहीं था कि वे इसका विरोध कर पाते। बेरोजगारी समूचे देश में है और सभी जातियों व समूहों में हैं। इसी प्रकार गरीबी भी सभी जातियों व समूहों में है परन्तु बेरोजगारी को समाप्त करना सबके लिये काम की मांग करना यह आसान नहीं है। इसके लिये तो सारे निजाम को बदलना

होगा। और इसलिये यह आसान मांग है कि किसी एक आरक्षित समूह में जहां मुकाबला कमजोर से हो वहां प्रवेश कर छोटी मोटी हिस्सेदारीयाँ लेना कुछ अपने जाति समूह के लोगों को बड़े पदों पर बैठा लेना यह आसान प्रक्रिया होती है। यही मार्ग राजस्थान में गुर्जर समाज ने अपनाया और उसके लिये भारी कुर्बानी दी जिसमें 70 से अधिक लोग मारे गये थे कई महीनों तक रेल गाड़ियां बंद रही थी इसके बावजूद वह अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो पाये थे। ऐसी ही मांग देश के अलग-अलग भागों में उठती रहती है। परन्तु गुर्जर समाज के परिणाम देखने के बाद अब कोई बड़ा संघर्ष जातीय समूहों ने नहीं किया है। मैतेई समाज भी कोई संघर्ष नहीं कर रही थी और मणिपुर में जो हुआ वह मांग का संघर्ष नहीं है बल्कि मांग के प्रतिकार का संघर्ष है। जिससे न मैतेई समाज को न राय को कुछ हासिल हुआ बल्कि एक स्थाई घाव बन गया। अब यह कितने वर्षो में भरा जायेगा या इसके भावी परिणाम क्या होंगे इसका आंकलन करना कठिन है वैसे नागा व कूकी समुदाओं का एक हिस्सा प्रथकता समर्थक रहा है और इस घटना से उसे प्राणवायु मिली है।

मेरी राय में अब समाज और सरकार को निम्न मुद्दों पर विचार कर निर्णय करना चाहिये।

1- जातिगत व धार्मिक आदिवासी समूहों की जातिगत और समूह गत जनगणना हो।

2- उच्च तकनीकी वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ज्ञान के विषयों और रोजगारों को छोड़कर बकाया सरकारी और निजी नौकरियों में जातियों व समूहों की संख्या के अनुपात में भागीदारी हो।

3- जिनके पास सरकारी नौकरी या अन्य कोई कम धंधा नहीं है उन बेरोजगारों को 5000 रूपये प्रतिमाह की दर से न्यूनतम बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।

4- सभी चयन परीक्षाओं या आयोजनों को विकेन्द्रित कर तहसील स्तरों पर किया जाये तथा चयनित परीक्षा आदि के लिये परीक्षा शुल्क की स पूर्ण पद्धति समाप्त हो। डॉ. लोहिया ने 50 के दशक में कहा था कि कम से कम 60 प्रतिशत पिछड़ों की हिस्सेदारी हो। और अब यह कहना होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी।

इस नीतिगत फैसले से राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होगी और राजनीति भी छोटे सवालों से हटकर बड़े लक्ष्यों पर केन्द्रित हो सकेगी। आरक्षण के पक्ष-विपक्ष के धुवीकरण से भी देश बच सकेगा।

Marriage with a workaholic

Should workaholic professionals and CEOs not plan a vacation, Every 6 months, with their families?

Like many professionals, I love my boss for a few good reasons: That he is a workaholic; that is very disciplined; that he has a busy schedule throughout the year; and that he is very focused.

All there are, perhaps, the common traits among the breed called CEOs. My boss is one of them. In 25 years, he has been able to establish an institution that has branches in 5 foreign countries, in addition to 7 centers in India.

At the age of 58,he is the busiest person in our organizations, or perhaps one of most devoted persons I have ever seen in my life. He receives no less that 300 mails everyday, and replies to most of them. In addition, he does myriad other works like meetings, administration, financial control, writing articles in newspapers and foreign tours.

We were surprised when he sent us an all-staff mail that he was going on a week's vacation, as absence from work was something not part of in his life. He often gave us a mild scolding whenever we asked for a few days leave. He knew he was asking something that in not viable, but he liked to see his persona in others. In the evening, when I asked him about his vacation tour, his answer was short: He was off for some day as with wife, to Shimla.

In spite of working with him for more than 5 years, I have not been able to decipher how things were between him and his wife. I did wonder how he coped with the conjugal relationship while working even on Sundays.

I say this because, whenever I am called on a Saturday to do urgent work, my wife gets angry. She does not like our weekends or holidays,-which are no many in private firms-to be consumed

by office or any other assignments. And a happy wife is essential for a happy life.

Seeing me a little confused at his decision, he asked me to sit down. After a brief pause and a few puffs at a cigar, he said that his was the most stressful life. As he has no time to devote to his wife, he felt helpless and hapless. But he had no other option any more. With the expansion of his organizations, his business had increased many times, which consumed all his time...........

As he went on talking about his private life, I discovered how unfortunate he was! When, after a day's work, he reached home, he usually found his wife seething in suppressed anger. And being tired to the hilt, he would be in no mood to crack jokes, or even smile properly, while his wife wanted to talk about sundry things and issues.

He did rallies that women love to be with their husbands in advanced age and that he had not been able to provide company to his wife.

"You know, she cites the example of our neighbors-- the Transport Commissioner. How he maintains his official duties and how he comes home by evening and plays with children," my boss laughed a bitter laugh.

I could understand what he meant. The difference between Government officials and entrepreneurs is the difference of a sense of ownership.

Pragmatic decision

Without doubt, busy men's wives are not happy. And if the husbands happen to be young CEOs, they have bigger reasons for worry. Suspicion of involvement with the private secretary can lead to mental agony for the women, who are waiting at home. In case of young women bosses, things can be all the more precarious.

It is, however, not galway elicit relationship or occasional sexual relationship that is the sole concern of wives and husbands; it is the general worry of living in a big, of unexpected incidents like blasts and accidents and stress-related to work that add to concerns.

Coming back to my boss'

miserable conjugal life, he was rather tense that day. He seemed to have raised, perhaps for the firs time, that he had to do something to save his personal life.

His wife was not happy with his perennial hectic schedules throughout the year, and he had to find some time for his family. From his talk, I could make out that my boss was suffering from the loss of intimacy with his wife. Sexual alienation is common in workaholic couples, which might lead to breakdown or divorce.

The workaholic, in principle and in practice, becomes married to his job. While utmost commitment to work yields handsome pay-offs, loss of commitment to the life partner comes in the from of the biggest loss.

Loss of humor and the ability to be a playful mood was also visible. Since the loss of energy and vitality is so huge among workaholic, they hardly like to speak a word when they enter their residential premises. As a result, life becomes overly serious, melancholic and empty of meaning.

While the workaholic husband or wife-would prefer a calm and quiet environment at home, the other half and the children would love to talk and play since that is the time the family is together. Irritation at once takes over a weary man or woman once the kids try to hug him or her and they are brushed aside with slight anger.

If this continues for a long time, it is highly likely that relations with children will also become sour. Much of the alienation among the teenagers, that we witness today, is due to the utter negligence of parents, who love their work more than their kids.

Increasing work pressure and a too-busy schedule can gradually blur the time line

between one's home and workplace, compelling news-age executive to devote little time for leisure or personal space. Most workaholic are unable to find a way to strike a balance between work and family time.

So, the decision of my boss to go on a week's vacation was not only an urgent necessity to save his married life, but also the essence of completeness among humans. One's duty is to look after the personal life as seriously as the professional one.

Important things

Thus, we have examples of authors, scientists and explores, who has been so engrossed in their artistic pursuit that they had to part with their spouses, or their married life failed miserably.

The studies on workaholism come to the lime light with the publication of Work Addiction Risk Test' by B.E. Robinson in 1999, which is detailed in his famous book chained to the Desk: A Guidebook for Workaholic, Their Partners and children, and the Clinicians Who Treat Them.

However, in 2006, S.J. Vodanovich and C. Piotrowski, in their research, showed that workaholism could impact diverse area of human functioning, such as individual, family, organizational, and societal levels. Researchers have concluded that work addiction is identical to an addiction to alcohol, which leads to unman age able life, family disintegration, serious health problems, etc.

integration, serious health problems, etc Other maladies include obsessive-compulsiveness, perfectionism, and typical behaviors. The most common after effects of

workaholism can be rapid health determination, job stress, work family conflict, teamwork problem (as no all employees would follow the workaholic), job performance, aloofness from family interactions, problems in communication, lack of enjoyment of life and leisure time.

The busiest of men on earth must keep in mind that there are more important things than money in this world, Just as delaying an important meeting is critical for your professional growth, delay in reaching home for a family outing or dinner would, if it was promised, is equally serious.

Meeting a professional deadline is as important as fulfilling personal obligations. Both- husband and wife-need to sit and chalk out a plan of action as to how to get the time out of the busy schedule, rather than adopt an approach that could lead conflict and confrontation.

Some professionals do serous work, finish the day's work as per plan, but like to spend some time with friends at some restaurant for refreshment. This is asking for problems.

And equally undesirably is the behaviors of a wife if she starts blaming her husband once he enters the home premised. Nagging or blaming your spouse for not finding time for your may make it even more difficult to move towards a comprehensible solution.

The conversation should not focus on the spouse's failure to strike a balance between work and family, but on the desired attention and family time. In Delhi, as in other metros, working men do often come home late, but it is not advisable to bring the office into home premises. A workaholic, like my boss, reaches home and still talks about office on the phone or opens up the laptop for replying mails.

As I was grappling with how my boss had faced life, I knew our Director was moving in the right direction by going on a week's leave to the I Himalayas. And in his last mail he wrote thus: "Please no calls, no mails and no communication except in extreme emergency."

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.